सांध्य दैनिक
नई दृष्टिबिंदु
सच की शक्ति, जनता की दृष्टि

PRGI Reg No - CTHIN/25/A3746

सु-विचार

उल-झन से भरी इस दुनिया में खुशहाल जीवन जीना भी किसी कामयाबी से कम नहीं... । ....अज्ञात

वर्ष–01 अंक–15 | संपादक आलोक तिवारी | दुर्ग, सोमवार 02 फरवरी 2026 | पृष्ठ 08 | मूल्य –2 रुपए,

रजिस्ट्रार ने रद्द किया ट्रस्ट मंडल चुनाव, नियमों को रौंदकर हुई प्रक्रिया उजागर

11 लाख दो, ट्रस्टी बनो! देव आनंद जैन शिक्षण संघ में चुनाव बना सौदेबाजी

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

शिक्षा के नाम पर संचालित संस्था श्री देव आनंद जैन शिक्षण संघ में ट्रस्ट मंडल का चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि पैसे का खेल बन चुका था। रजिस्ट्रार फर्म्स एवं संस्थाएं, छत्तीसगढ़ के आदेश ने इस कड़वे सच पर मुहर लगा दी है। 16 जून 2024 को कराए गए ट्रस्ट मंडल के चुनाव को पूरी तरह नियम विरुद्ध पाते हुए रजिस्ट्रार ने उसे निरस्त कर दिया।

फाइलों में दर्ज सनसनीखेज शर्त

जांच में सामने आया कि– ट्रस्ट मंडल का सदस्य बनने के लिए 11,00,000/- का चेक देना अनिवार्य किया गया। हैरानी की बात यह कि– यह शर्त संघ की पंजीकृत नियमावली में कहीं नहीं है न सामान्य सभा से इसकी स्वीकृति ली गई, न सदस्यों को लिखित जानकारी दी गई, यानी ट्रस्टी पद खरीदने का रास्ता खोला गया।

शिकायतकर्ता बोले -यह चुनाव नहीं, वसूली थी

संघ के आजीवन सदस्य अमरचंद सुराना ने शिकायत में कहा कि– यदि 11 लाख का चेक नहीं दोगे तो चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। उन्होंने इसे सदस्यता के अधिकार का खुला हनन बताया।

बड़ा सवाल : पैसा गया कहाँ?

अब सबसे अहम सवाल– 11 लाख के चेक किस खाते में गए? उनका उपयोग किस उद्देश्य से हुआ ?क्या यह राशि वापस की गई? संस्था को दान की राशि वापसी पर कौन से नियमों का उल्लंघन रजिस्ट्रार ने इस राशि से जुड़े प्रमाणिक दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।

शिक्षा संस्थानों में चुनावी ठेका संस्कृति?

विशेषज्ञों का कहना है कि– यदि ऐसे मामलों पर सख्ती नहीं हुई तो शैक्षणिक संस्थाएं ट्रस्ट नहीं, ठेके बन जाएँगी। यह मामला केवल एक संस्था तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के लिए चेतावनी है।

अब अगला कदम

सूत्र बताते हैं कि– मामले की वित्तीय जांच की तैयारी, अन्य सदस्यों द्वारा अलग शिकायतें आवश्यक हुआ तो आपराधिक कार्यवाही की मांग की जा रही हैं।

रजिस्ट्रार का सख्त फैसला

रजिस्ट्रार ने अपील, जवाब, लिखित तर्क और सुनवाई के बाद साफ कहा कि– निर्वाचन प्रक्रिया अवैध एवं असंवैधानिक है। 11 लाख की शर्त नियमों के विपरीत है। चुनाव तत्काल प्रभाव से निरस्त किए जाते हैं। संघ को नियमों के अनुसार नही चलने की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच अधिकारी की नियुक्ति।

मतदाता सूची गायब, चुनाव मनमर्जी से

दस्तावेज बताते हैं कि—मतदाता सूची प्रकाशित नहीं की गई, चुनाव कार्यक्रम की पारदर्शी सूचना नहीं दी गई, सचिव द्वारा मनमाने ढंग से सदस्यों का चयन किया गया। विरोध करने वाले सदस्यों को चुनाव से बाहर रखने की धमकी तक दी गई। यह पूरी प्रक्रिया नियम– 15 और नियम–8 का सीधा उल्लंघन है।

सामूहिक दुष्कर्म मामले में एक और गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

नाबालिग पीड़िता से जुड़े दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म के गंभीर प्रकरण में महिला थाना दुर्ग पुलिस को एक और बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने इस मामले में एक अतिरिक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह मामला वर्ष 2018 से 11 अक्टूबर 2025 के मध्य घटित घटनाओं से संबंधित है, जिसमें नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म एवं सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं हुई थीं। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए महिला थाना दुर्ग द्वारा लगातार विवेचना की जा रही थी।

जांच के दौरान एक अन्य आरोपी की संलिप्तता प्रमाणित होने पर उसे चिन्हित किया गया। इसके बाद आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई तथा विधिवत गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपी की पहचान गोविंद सिंह नागवंशी (62 वर्ष), निवासी चौकड़िया पारा, वार्ड क्रमांक 35, जिला राजनांदगांव के रूप में हुई है। पुलिस ने बताया कि मामले में इलेक्ट्रॉनिक एवं अन्य साक्ष्यों की जांच जारी है। वहीं, शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रकरण में संलिप्त किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा और सभी के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

सैकड़ों मजदूरों ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

भिलाई। मेहनतकश आवास अधिकारों संघ, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा मजदूर कार्यकर्ता समिति द्वारा हॉस्पिटल सेक्टर के सैकड़ों मजदूरों ने जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा।

ज्ञापन के माध्यम से प्रमुख रूप से यह मांग रखी गई कि हॉस्पिटल सेक्टर के निवासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाए तथा सेक्टर के आसपास उपलब्ध खाली भूमि पर उन्हें बसाया जाए। संगठन ने बताया कि भिलाई इस्पात संयंत्र (बीएसपी) के पास हजारों एकड़ भूमि उपलब्ध है, जिसे अन्य कार्यों के लिए आवंटित कर दिया गया है, लेकिन संयंत्र में कार्यरत मजदूरों के आवास हेतु आज तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई।

मजदूरों ने जिला कलेक्टर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन से मिलने की गुहार लगाई। मेहनतकश आवास अधिकार संघ समिति का कहना है कि नगर निगम भिलाई, जिला प्रशासन, भिलाई इस्पात संयंत्र तथा मुख्यमंत्री आपसी समन्वय से बातचीत कर इस गंभीर आवास समस्या का स्थायी समाधान निकालें। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि एक सप्ताह के भीतर ठोस पहल नहीं की गई, तो हॉस्पिटल सेक्टर के हजारों श्रमिक महिला-पुरुष, बच्चे सहित रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर अपनी मांग रखेंगे। इस प्रदर्शन में प्रमुख रूप से चमेली, के. बाल्लमा, संजना, इसरात अम्मा, सुमरीत सुंदरियां, मुकेश, प्रेम किशन, अरुण्णा, अगरौतीन, ओमप्रकाश साहू, प्रेमा, वाई. शुशीला, ब्रह्मा, बी. कृपावती, पी. विमलम्मा, निरा, बी. कोंडम्मा, कलादास डेहरिया, नारायण राव सहित सैकड़ों मजदूर उपस्थित थे।

निवेशकों को तगड़ा झटका, विशेषज्ञ बोले—घबराने की जरूरत नहीं

केन्द्रीय बजट के बाद बाजार में आया भूचाल सेंसेक्स लुढ़का, सोना-चांदी गिरी धड़ाम से

संदीप सिंह / नईदिल्ली

1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निमर्ला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट के बाद शेयर बाजार और कीमती धातुओं में जबरदस्त हलचल देखने को मिली। बजट के दिन जहां शेयर बाजार बुरी तरह डगमगाया, वहीं सोना-चांदी की कीमतों में भी ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की गई। बाजार की इस प्रतिक्रिया ने निवेशकों की चिंता बढ़ा दी है, हालांकि विशेषज्ञ इसे अस्थायी झटका मान रहे हैं।

शेयर बाजार में आई भारी गिरावट

बजट के दिन शेयर बाजार में जबरदस्त उतार-चढ़ाव देखने को मिला। शुरुआती बढ़त के बाद सेंसेक्स और निफ्टी अचानक फिसल गए।

Groww के आंकड़ों के अनुसार– सेंसेक्स करीब 1,800 अंक तक टूट गया। निफ्टी में 500 अंकों से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। इस गिरावट से निवेशकों के करोड़ों रुपय डूब गए। विशेषज्ञों के अनुसार, गिरावट के प्रमुख कारण रहे– STT (सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स) में बढ़ोतरी, मुनाफावसूली (प्रॉफिट बुकिंग), बायबैक टैक्स नियमों में बदलाव, इन फैसलों से बाजार की धारणा पर नकारात्मक असर पड़ा। सोना और चांदी में ऐतिहासिक गिरावट, बजट के बाद कीमती धातुओं के बाजार में भी भूचाल आ गया।

सोना

सोने की कीमत में 3,560 से लेकर 15,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक की गिरावट दर्ज की गई।

MCX पर सोना अपने रिकॉर्ड स्तर से करीब 18 प्रतिशत नीचे आ गया।

चांदी

चांदी के दाम में करीब 72,500 रुपये प्रति किलो की गिरावट आई।

इससे इसकी कीमत घटकर लगभग 3.12 लाख रुपये प्रति किलो रह गई।

गिरावट के कारण

विशेषज्ञों के अनुसार–अमेरिकी डॉलर की मजबूती, फेड रिजर्व की नीतियों पर अटकलें, आयात शुल्क में कोई बदलाव नहीं, इन कारणों से सोने-चांदी पर दबाव बढ़ा।

बाजार की नकारात्मक प्रतिक्रिया क्यों?

विश्लेषकों का मानना है कि बजट में कुछ ऐसे फैसले हुए, जिनसे निवेशकों में असमंजस पैदा हुआ– STT में वृद्धि, शेयर बायबैक पर टैक्स सख्ती, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग पर दबाव, इन कारणों से निवेशकों ने तेजी से बिकवाली की।

अर्थव्यवस्था पर बजट का दीर्घकालीन असर

हालांकि बाजार की शुरुआती प्रतिक्रिया नकारात्मक रही, लेकिन अर्थव्यवस्था को लेकर विशेषज्ञों का नजरिया संतुलित है।

विकास दर में स्थिरता

आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार– 26 में GDP ग्रोथः 7.4%, 27 में अनुमानः 6.8 से 7.2%, सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12.22 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड प्रावधान किया है।

राजकोषीय अनुशासन पर जोर

सरकार ने वित्तीय मजबूती का संकेत देते हुए–राजकोषीय घाटा 4.3% पर सीमित करने का लक्ष्य रखा, महंगाई घटकर 1.7% के स्तर पर बताया है। इससे विदेशी निवेशकों में भरोसा बढ़ने की उम्मीद है।

प्रमुख सेक्टरों पर असर

MSME और स्टार्टअप, 10,000 करोड़ का रटए ग्रोथ फंड, 2,000 करोड़ की लिक्विडिटी सहायता

कृषि क्षेत्र

कृषि बजट बढ़कर 1.62 लाख करोड़
अकआधारित टूल भारत-विस्तार लॉन्च

मध्यम वर्ग

इनकम टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव नहीं
TCS और TDS नियम सरल

निवेशकों के लिए क्या है संदेश ?

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा गिरावट अस्थायी है।
उनका कहना है– यह गिरावट लंबी अवधि के निवेशकों के लिए अवसर हो सकती है।

घबराकर बिकवाली से बचें

मजबूत कंपनियों में निवेश बनाए रखें
विशेषज्ञों के अनुसार, बजट का फोकस उपभोग के बजाय विनिर्माण और आपूर्ति पक्ष को मजबूत करने पर है, जिसका असर आने वाले वर्षों में दिखेगा।

झटके के बाद संतुलन की राह

केंद्रीय बजट 2026-27 के बाद बाजार को भले ही तात्कालिक झटका लगा हो, लेकिन सरकार की रणनीति दीर्घकालीन मजबूती पर केंद्रित है। शेयर बाजार और कीमती धातुओं में आई गिरावट को विशेषज्ञ अस्थायी मान रहे हैं। आने वाले महीनों में इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश, औद्योगिक विस्तार और आर्थिक सुधारों का असर बाजार में दिखने की उम्मीद है।

गांजा तस्करी करते 2 आरोपी गिरफ्तार

भिलाई। 1फरवरी को थाना जामुल पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि छावनी बस्ती क्षेत्र में दो व्यक्ति अवैध रूप से मादक पदार्थ गांजा की बिक्री कर रहे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम द्वारा तिरंगा चौक, छावनी के पास घेराबंदी की गई। पुलिस को देखकर दोनों संदेही भागने का प्रयास करने लगे, जिन्हें घेराबंदी कर मौके पर ही पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपियों द्वारा अपना नाम कल्याण वर्मा एवं लोकेश उइके बताया गया। आरोपियों के कब्जे से अवैध रूप से 01 किलो 530 ग्राम गांजा, नगद राशि एवं मोबाइल फोन जप्त किया गया, जिसकी कुल अनुमानित कीमत लगभग 80,000 रुपये है। मामले में अपराध क्रमांक 70/2026 धारा 20(ख), 27(क), 29 एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार किया गया तथा न्यायालय में प्रस्तुत कर केंद्रीय जेल दुर्ग भेजा गया है।

दहशत मुठभेड़ में मास्टरमाइंड घायल, 2 रातों में 5 वारदात, 13 घायल, 8 आरोपी गिरफ्तार

जांजगीर में खाकी का कहर, बदमाशों पर टूटा कानून का कहर

नई दृष्टिबिंदु / जांजगीर-चांपा

जिले में लगातार लूट, मारपीट और जानलेवा हमलों से दहशत फैलाने वाले गिरोह पर जांजगीर-चांपा पुलिस ने बड़ी और निर्णायक कार्रवाई करते हुए करारा प्रहार किया है। थाना शिवरीनारायण और पामगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि गिरोह का मास्टरमाइंड रामनाथ पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस घेराबंदी के दौरान आरोपी रामनाथ ने देशी कट्टे से पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने आत्मरक्षा में कार्रवाई करते हुए उसके पैर में गोली मारी। घायल आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर उपचार हेतु अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह मुठभेड़ पुलिस की सख्त कार्यप्रणाली और अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति का स्पष्ट संदेश है।

दो रातों में दहशत, पांच जगह हमला

27 और 29 जनवरी की दरम्यानी रात गिरोह ने थाना शिवरीनारायण और पामगढ़ क्षेत्र में पांच अलग-अलग स्थानों पर वारदात को अंजाम दिया। आरोपियों ने सुनसान रास्तों पर राहगीरों को रोककर लोहे की रॉड, डंडा और

बेल्ट से बेरहमी से हमला किया। इन घटनाओं में कुल 13 लोग घायल हुए, जिनमें से दो की हालत गंभीर बनी हुई है। एक युवक कोमा में है, जिसका इलाज रायपुर और बिलासपुर में जारी है। लगातार हो रही घटनाओं से क्षेत्र में भय का माहौल बन गया था।

विशेष टीम बनाकर पुलिस ने तोड़ा नेटवर्क घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में विशेष जांच टीम गठित की गई। टीम ने सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपियों की पहचान की। लगातार दबिश देकर पुलिस ने एक-एक कर सभी आरोपियों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। फरार मास्टरमाइंड को भी मुठभेड़ के बाद पकड़ लिया गया। पुलिस की त्वरित कार्रवाई से अपराधियों का नेटवर्क पूरी तरह ध्वस्त हो गया। खतरनाक अपराध पैटर्न, सुनियोजित गिरोह पूछताछ में सामने आया है कि गिरोह का तरीका अत्यंत क्रूर और संगठित था। आरोपी मोटरसाइकिलों से अंधेरे रास्तों पर घूमते थे और राह चलते लोगों को रोककर सीधे सिर पर हमला करते थे। पीड़ितों को गंभीर रूप से घायल कर मोबाइल, नकदी और अन्य सामान लूट लिया जाता था। इसके बाद आगे बढ़कर अगले शिकार को निशाना बनाया जाता था। लगातार हमलों से क्षेत्र में दहशत फैलाना इनका मुख्य उद्देश्य था।

चार लाख से अधिक की संपत्ति जब्त

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी मात्रा में आपराधिक सामग्री बरामद की है, जिसमें स्टील रॉड, लोहे के पाइप, डंडा, बेल्ट, मोटरसाइकिल, स्कूटी, मोबाइल फोन और नगद राशि शामिल है। जब्त सामग्री की कुल कीमत लगभग चार लाख नौ हजार रुपये आंकी गई है। गंभीर धाराओं में दर्ज प्रकरण, सभी आरोपी जेल भेजे गए आरोपियों के विरुद्ध बीएनएस की गंभीर धाराओं के तहत विभिन्न थानों में प्रकरण दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। विधि से संघर्षरत बालकों के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि इस मामले की विवेचना पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ की जा रही है।

पुलिस का सख्त संदेश

अपराध करोगे तो अंजाम तय इस कार्रवाई के माध्यम से जांजगीर-चांपा पुलिस ने अपराधियों को कड़ा संदेश दिया है कि जिले में लूट, हिंसा और गैंग अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस प्रशासन ने साफ किया है कि कानून से टकराने वालों के लिए जेल और अस्पताल के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। अपराधियों को चेतावनी दी गई है कि यदि भविष्य में ऐसी किसी भी गतिविधि में संलिप्त पाए गए तो और कठोर कार्रवाई की जाएगी।

जनता में बढ़ा भरोसा, पुलिस की सराहना

लगातार हो रही वारदातों से परेशान आम नागरिकों ने पुलिस की इस कार्रवाई पर संतोष व्यक्त किया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि अब उन्हें सुरक्षा का भरोसा मिला है। पुलिस की सक्रियता से क्षेत्र में शांति और विश्वास का माहौल बनने लगा है। जांजगीर में अब कानून का राज जांजगीर–चांपा पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई ने साबित कर दिया है कि अपराध चाहे जितना संगठित क्यों न हो, कानून से बचना संभव नहीं है। खाकी अब पूरी मजबूती के साथ मैदान में है। अपराधियों की उलटी गिनती शुरू हो चुकी है। जिले में अब कानून का राज स्थापित किया जा रहा है।

विकसित भारत की दिशा में ऐतिहासिक कदम- मुख्यमंत्री साय

आमजन का पुलिस पर विश्वास व अधिक सुदृढ़ हो और असामाजिक तत्वों व बदमाशों के हौसले पस्त हों

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट भारत के सुनहरे और विकसित भविष्य की दिशा में एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। कर्तव्य भवन में बना हुआ यह पहला बजट है, जिसमें देश के समग्र विकास और प्रत्येक नागरिक के कल्याण को ध्यान में रखते हुए तीन प्रमुख कर्तव्यों-आर्थिक विकास एवं रोजगार वृद्धि, जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति तथा ह्यसबका साथ, सबका विकासह्ल को केंद्र में रखा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को इस बजट का सीधा लाभ मिलेगा।

कृषि व ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती

बजट में किसानों की आय बढ़ाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। एआई और आधुनिक तकनीक के माध्यम से कृषि उत्पादकता बढ़ाने, पशुपालन एवं डेयरी उद्योग को प्रोत्साहन देने की योजना बनाई गई है। साथ ही महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल के तहत स्थानीय उद्योग और हस्तशिल्प को बढ़ावा देकर ग्रामीणों के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट में युवाओं के लिए रोजगार सृजन पर विशेष जोर दिया गया है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में नए अवसर पैदा होंगे। पर्यटन को बढ़ावा देने से स्थानीय आर्थिक विकास को गति मिलेगी और युवाओं को अपने ही क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। विदेश यात्रा और विदेशों में पढ़ाई भी पहले की तुलना में सस्ती होगी।

स्वास्थ्य क्षेत्र में ऐतिहासिक पहल

स्वास्थ्य क्षेत्र को लेकर बजट को ऐतिहासिक बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जिससे कैंसर, डायबिटीज सहित अन्य गंभीर बीमारियों की दवाइयां सस्ती होंगी। जिला अस्पतालों के उन्नयन, हर जिले में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर की स्थापना, मानसिक स्वास्थ्य और आयुर्वेदिक चिकित्सा को बढ़ावा देने के साथ-साथ मेडिकल टूरिज्म के लिए राज्यों में पांच रीजनल हब स्थापित किए जाएंगे। इससे छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सेवाओं का स्तर बेहतर होगा और रोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे।

महिला सशक्तिकरण को नई दिशा

लखपति दीदी योजना के विस्तार के माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट-लिंक्ड स्वरोजगार, उद्यमिता और स्थानीय बाजार से जोड़ने की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा हर जिले में बालिकाओं के लिए छात्रावास निर्माण की घोषणा से उन्हें उच्च शिक्षा में सहायता मिलेगी।

उद्योग, शिक्षा और खेल को बढ़ावा

देश की आर्थिक मजबूती के लिए 7 हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जलमार्ग, बड़े टेक्सटाइल पार्क और 4 राज्यों में खनिज कॉरिडोर की घोषणा की गई है। सेमीकंडक्टर मिशन के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के निवेश से औद्योगिक विकास और रोजगार को नई गति मिलेगी। वहीं खेलो इंडिया मिशन और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों से बच्चों और युवाओं को बेहतर अवसर मिलेंगे।

कर सुधार और आम जनता को राहत

आयकर प्रक्रिया को सरल बनाया गया है और छोटे करदाताओं के लिए आसान व्यवस्था की गई है। दवाइयां, कपड़े, जूते, मोबाइल, ईवी बैटरी, सोलर उपकरण, बायोगैस-सीएनजी सहित कई रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती होंगी, जिससे आम जनता को सीधी राहत मिलेगी।

अंत में मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की भावना को और मजबूत करता है। यह बजट छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण को इस ऐतिहासिक, विकासशील और जनकल्याणकारी बजट के लिए हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित किया।

केंद्रीय बजट आम आदमी का नहीं औद्योगिक घरानों का बजट - दीपक बैज

केंद्रीय बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वित्त मंत्री निमर्ला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट देश की जनता को निराश करने वाला तथा कारपोरेट घरानों को समर्पित बजट है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए बजट में कुछ नहीं है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि छत्तीसगढ़ की एक बार फिर उपेक्षा हुई है। डबल इंजन की सरकार ने छत्तीसगढ़ को ठगा है। छत्तीसगढ़ के कोयला और खनिज संसाधनों के दोहन के लिए कोरिडोर बनाने की बात की गयी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के विकास के लिए राज्य को कुछ नहीं मिला। देश की सर्वाधिक कोयला, आयरन ओर, बाक्साईट देने वाले छत्तीसगढ़ की इस बार भी मोदी सरकार ने उपेक्षा किया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि महंगाई कम करने, नये रोजगार सृजन और करों को छूट देने में यह बजट नाकाम साबित हो गया है। बजट से युवा और छोटे व्यापारी निराश हुए है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि वित्त मंत्री ने बजट में एक बार फिर झूठा दावा किया कि 25 करोड़ लोगों को इन्होंने गरीबी रेखा से बाहर निकाला जबकि आज भी देश की आबादी का 61 प्रतिशत लोगों 81 करोड़ को सरकार 5 किलो राशन देने का दावा करती है।

बजट से देश का विकास रुकेगा, रोजगार घटेगा - सुशील आनंद शुक्ला

मोदी सरकार की अदूरदशिर्ता का प्रमाण है 2026 का केंद्रीय बजट। प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि इस बजट ने देश की जनता को निराश किया है। बजट से देश का विकास रुकेगा, रोजगार घटेगा। यह बजट बताता है कि मोदी सरकार के आने वाले साल भी देश की जनता के लिए अच्छा नहीं रहने वाला, बजट में कोई भी दूरदशिर्ता नहीं दिख रही। युवा, किसान, मजदूर, महिला सभी इस बजट से खुद को ठगा महसूस कर रहे है।

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि देश के युवा तो अब रोजगार की उम्मीद भी छोड़ चुके हैं देश की कार्यशक्ति में महिलाओं की भागीदारी लगातार घटती जा रही है किसानों की आय दुगुनी करने की गारंटी दी थी लेकिन किसानों की आमदनी लगातार कम होती जा रही है और कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और लगातार किसानों की आत्महत्या की खबर आ रही है भाजपा की जुमला नीति से महंगाई की मार लगातार बढ़ती जा रही है ना गैस सिलेंडर के दाम कम हुए ना खाद्य पदाथी के दाम कम करने को लेकर कोई प्रयास इस बजट में नजर आया परिवारों की बचत खाली होती जा रही है अपना घर चलाने के लिए भी लोगो को जद्दोजहद करना पड़ रहा है।

केंद्रीय बजट 2026-स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने जताया आभार

केंद्रीय बजट 2026 को चिकित्सा और स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक बताते हुए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह बजट देश की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत, आधुनिक और सवर्सुलभ बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए लिए गए दूरदर्शी निणर्यों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बजट में औषधि प्रशिक्षण शालाओं की स्थापना का निर्णय दवा निर्माण और गुणवत्ता सुधार में अहम भूमिका निभाएगा। आयुष सेक्टर को सशक्त करते हुए तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की स्थापना से पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों को वैश्विक पहचान मिलेगी। कोविड-19 के बाद आयुर्वेद को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मिली स्वीकार्यता को ध्यान में रखते हुए आयुर्वेद उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई ठोस कदम उठाए जाएंगे।

केंद्रीय बजट समावेशी विकास और महिला सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम : मंत्री राजवाड़े

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े ने इसे 'समावेशी विकास, सामाजिक न्याय और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव रखने वाला जनहितैषी बजट' बताया है। श्रीमती राजवाड़े ने कहा कि यह बजट गरीब, किसान, युवा और महिलाओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है। शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण एवं उद्यमिता को समान रूप से प्राथमिकता देकर देश के सर्वांगीण विकास को नई गति प्रदान की गई है। उन्होंने महिला सशक्तिकरण से जुड़ी घोषणाओं की सराहना करते हुए कहा कि प्रत्येक जिले में महिला छात्रावास के निर्माण से छात्राओं एवं कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध होगा, जिससे शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी और अधिक सशक्त होगी।

वन उत्पादों के व्यापार को प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण-आदिवासी अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती : वनमंत्री केदार कश्यप

केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत आम बजट में तेंदूपत्ता उद्योग से जुड़े लाखों लोगों के हित में एक ऐतिहासिक और राहतपूर्ण निर्णय लिया गया है। सरकार ने तेंदूपत्ता व्यापार पर लगने वाली टीसीएस की दर को 5 प्रतिशत से घटाकर मात्र 2 प्रतिशत कर दिया है। इस महत्वपूर्ण निर्णय के सम्बन्ध में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि इस निर्णय से तेंदूपत्ता संग्राहकों, प्राथमिक सहकारी समितियों, लघु व्यापारियों और वन आधारित आजीविका से जुड़े परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। दर घटने से यह समस्या काफी हद तक समाप्त होगी और वन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। वनमंत्री केदार कश्यप ने इस जन-हितकारी फैसले के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा यह निर्णय दर्शाता है कि केंद्र सरकार देश के वनवासी, आदिवासी और श्रम आधारित उद्योगों की आर्थिक मजबूती को लेकर पूरी तरह संवेदनशील है।

वनमंत्री श्री कश्यप ने कहा कि तेंदूपत्ता उद्योग को इस फैसले से भरपूर लाभ मिलेगा। टीसीएस दर कम होने से तेंदूपत्ता व्यापार से जुड़े लोगों के हाथ में अधिक नकद राशि रहेगी, जिससे उनकी कायर्शील पूंजी मजबूत होगी। इसका सीधा लाभ तेन्दूपत्ता संग्राहकों मिलेगा। इसके साथ ही तेंदूपत्ता संग्रहण से जुड़े आदिवासी और वनवासी परिवारों को अब कम कर कटौती का सामना करना पड़ेगा, जिससे उन्हें उनके श्रम का पूरा मूल्य मिल सकेगा। वनमंत्री श्री कश्यप ने कहा कि पहले 5 प्रतिशत टीसीएस छोटे व्यापारियों के लिए बड़ा आर्थिक बोझ था। अब 2 प्रतिशत टीसीएस होने से व्यापार करना आसान और व्यावहारिक होगा। साथ ही कई संग्राहक और छोटे व्यापारी आयकर दायरे में नहीं आते थे, लेकिन टीसीएस कटने के बाद रिफंड की प्रक्रिया जटिल होती थी। दर घटने से यह समस्या काफी हद तक समाप्त होगी और वन आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। यह निर्णय तेंदूपत्ता जैसे वन उत्पादों के व्यापार को प्रोत्साहित करेगा और ग्रामीण-आदिवासी अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा। उन्होंने कहा कि यह बजट मानवीय और समावेशी बजट का उदाहरण यह फैसला इस बात का प्रमाण है कि मोदी सरकार का बजट केवल राजस्व बढ़ाने तक सीमित नहीं है, बल्कि गरीब, आदिवासी, श्रमिक और वन आश्रित समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने की स्पष्ट सोच के साथ तैयार किया गया है।

औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई दिशा देने वाला बजट : मंत्री लखन लाल देवांगन

वाणिज्य, उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम एवं श्रम मंत्री लखन लाल देवांगन ने केंद्रीय बजट 2026-27 पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ के औद्योगिक, कृषि और ग्रामीण विकास को नई गति देने वाला सिद्ध होगा। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य के अनुरूप औद्योगिक क्लस्टरों को पुनर्जीवित करने के लिए 2 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से राज्य में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों (टरटए) को सशक्त किया जाएगा, जिससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। श्री देवांगन ने कहा कि बजट में टरटएऔर बायोफार्मा सेक्टर के लिए 10 हजार करोड़ रुपये तथा सेमीकंडक्टर उद्योग के लिए 40 हजार करोड़ रुपये के प्रावधान से छत्तीसगढ़ में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ सहित देश के विभिन्न राज्यों में माइनिंग आधारित औद्योगिक कॉरिडोर, टेक्सटाइल और केमिकल पार्क की स्थापना से राज्य का मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत होगा। मंत्री श्री देवांगन ने कहा कि बैंकिंग क्षेत्र में सुधार, आर्थिक ऋण गारंटी और कर प्रक्रियाओं के सरलीकरण से राज्य के उद्यमियों, व्यापारियों और स्टार्टअप्स को पूंजी तक आसान पहुंच मिलेगी, जिससे उद्योग-हितैषी वातावरण बनेगा। मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्पोर्ट्स गुड्स सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ाने के प्रावधान से स्थानीय इकाइयों को सीधा लाभ मिलेगा।

किसान, गांव और आत्मनिर्भर भारत की मजबूत नींव - उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा

उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा ने आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक, अभूतपूर्व और विकसित भारत की दिशा में निर्णायक बताया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला और युवा देश की प्राथमिक आवश्यकताओं को केंद्र में रखकर तैयार किया गया है और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को नई मजबूती देता है। श्री शर्मा ने कहा कि किसानों के हित में बड़ा उर्वरक सब्सिडी का प्रावधान खेती की लागत घटाने वाला बड़ा कदम है। इससे सस्ता खाद-उर्वरक उपलब्ध होगा, उत्पादन लागत कम होगी और किसानों को सीधी राहत मिलेगी। साथ ही कृषि बजट को में समुचित प्रावधान किए जाने से कृषि अनुसंधान, नवाचार और आधुनिक तकनीकों को गति मिलेगी। ग्रामीण विकास पर 21 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि का उल्लेख करते हुए श्री शर्मा ने कहा कि यह बजट गांवों के समग्र विकास का स्पष्ट रोडमैप प्रस्तुत करता है।पंचायतों को दोगुनी सीधी सहायता, और विकसित ग्राम-स्वावलंबी ग्राम की परिकल्पना से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा मिलेगी। लखपति दीदी और रत्नए-मार्ट जैसी पहलों से स्वयं सहायता समूहों की बहनें आजीविका से आगे बढ़कर उद्यमी बनेंगी। उन्होंने कहा कि आज पेश केंद्रीय बजट 2026 यह स्पष्ट करता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश को मजबूत फैसलों और ठोस परिणामों के साथ आगे ले जा रही है।

केंद्रीय बजट 2026 पर्यटन एवं संस्कृति के लिए ऐतिहासिक उपहार : मंत्री राजेश अग्रवाल

केंद्रीय वित्त मंत्री निमर्ला सीतारामण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट 2026-27 को छत्तीसगढ़ के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने राज्य के विकास के लिए मील का पत्थर बताया है। उन्होंने कहा कि यह बजट पर्यटन को रोजगार इंजन बनाने और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर उजागर करने की दिशा में क्रांतिकारी कदम है, जो छत्तीसगढ़ जैसे समृद्ध सांस्कृतिक राज्य के लिए वरदान सिद्ध होगा। बजट में पर्यटन क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए राष्ट्रीय आतिथ्य संस्थान की स्थापना, प्रमुख पर्यटन हबों में गाइड प्रशिक्षण पायलट योजना और इकोलॉजिकल माउंटेन ट्रेल्स का विकास शामिल है। इसके अलावा, 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक पर्यटन गंतव्यों में बदलने तथा अंतरराष्ट्रीय यात्रा पर टीसीएस दर 2% घटाने से सस्ती यात्रा संभव होगी। छत्तीसगढ़ के इको-एथनिक पर्यटन, जनजातीय संस्कृति और राजिम कुंभ जैसे आयोजनों को इससे अपार लाभ मिलेगा। श्री अग्रवाल ने कहा कि "केंद्र सरकार का यह प्रयास छत्तीसगढ़ की पर्यटन संभावनाओं को साकार करेगा। हमारी राज्य सरकार मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में पहले ही पर्यटन नीति 2026 के तहत 350 करोड़ से अधिक निवेश आकर्षित कर चुकी है, और यह बजट इसे गति प्रदान करेगा। केंद्र की मदद से पहले ही पर्यटन स्थलों का विकास तेज हो चुका है।" राज्य में चित्रकोट, बस्तर की जनजातीय संस्कृति और सरगुजा के धार्मिक स्थलों को इको-टूरिज्म और सांस्कृतिक सर्किट के रूप में विकसित करने का सुनहरा अवसर मिला है। बजट से उत्पन्न रोजगार अवसर स्थानीय युवाओं के लिए वरदान होंगे, जबकि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल का राजस्व 5 गुना बढ़कर 10 करोड़ पहुंच चुका है। मंत्री श्री अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री की सराहना करते हुए कहा कि यह 'विकसित भारत' का सशक्त कदम है। श्री अग्रवाल ने राज्य स्तर पर भी कमर कसने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि "यह बजट न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगा, बल्कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करेगा," ।

शहर एवं गांवो के विकास पर आधारित जनहितकारी यह बजट-संजय सिंह

मोदी सरकार के बजट को आम जनता का बजट बताते हुए प्रदेश आर्थिक प्रकोष्ठ के कार्यालय सह प्रभारी संजय सिंह ने कहा कि शहर एवं गांवो के विकास पर आधारित जनहितकारी यह बजट गांवों के आर्थिक विकास के साथ ही देश में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए हाईस्पीड रेलवे के साथ मेट्रो एवं एयरपोर्ट के विस्तार कि योजना से भारत की नई तस्वीर बनेंगी। रटए सेक्टर को मजबूत करने के लिए ?10,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं एवं केंद्रीय बजट में सेमीकंडक्टर क्षेत्र के लिए 40 हजार करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। चिप मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से भारत में युवाओं को रोजगार के नए अवसर के साथ ही लाखों नई नौकरियां मिलेंगी।महिलाओं के आर्थिक विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। किसानों के आय बढ़ाने के लिए आधुनिक कृषि उत्पादन के साथ आधुनिक तकनीकों से पशुपालन व्यवसाय को लाभ होगा । रेशम, ऊन, जूट जैसी प्राकृतिक फाइबर के साथ-साथ मैन-मेड और नई औद्योगिक-युग की फाइबर में आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। जीवन रक्षक दवाओं को सस्ता करने के साथ ही स्वास्थ्य संस्थानों को अपग्रेड किया जाएगा और नए संस्थान स्थापित किए जाएंगे। ऑप्टोमेट्री, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया, ओटी टेक्नोलॉजी और बिहेवियरल हेल्थ जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है।

जिले में विभिन्न वर्गों ने केन्द्रीय बजट पर दी अपनी -अपनी प्रतिक्रिया

नई दृष्टिबिंदु / राजनांदगांव

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण ने संसद में वर्ष 2026-27 के लिए केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। कर्तव्य भवन में तैयार यह बजट कर्तव्यों से प्रेरित है। जिनमें देश में आर्थिक विकास को तेज करना और उसकी गति बनाए रखना, भारत की समृद्धि के पथ में सशक्त साझेदार बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना तथा सरकार की सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण से संसाधनों, सुविधाओं और अवसरों तक पहुंच सुनिश्चित करना है। केन्द्रीय बजट की जिले में चर्चा रही और विभिन्न वर्गों के लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की।

सरकार का यह बजट दूरदर्शी एवं दूरगामी बजट : व्यापारी राधेश्याम गुप्ता

जिले के व्यापारी राधेश्याम गुप्ता ने कहा कि सरकार का यह बजट दूरदर्शी एवं दूरगामी बजट है। उन्होंने कहा कि उन्हें 500 जलाशयों एवं अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास की पहल बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण एवं जल संवर्धन के लिए सरकार की यह पहल बहुत अच्छी प्रशंसनीय है। उन्होंने कहा कि वृद्धों की चिकित्सा और संबद्ध देखभाल सेवाओं को शामिल करते हुए मजबूत देखभाल सेवा परिवेश बनाया जाएगा। अगले कुछ वर्षों में डेढ़ लाख देखभाल सेवा प्रदाताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। यह बहुत प्रशंसनीय हैं।

डिजिटल, क्रिएटिव और तकनीकी कौशल सीखने के नए अवसर : डॉ. घमेन्द्र कुमार

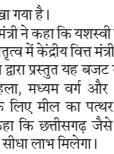

विद्यार्थी भौतिकी शोधकर्ता डॉ. घमेन्द्र कुमार साहू ने कहा कि केन्द्रीय बजट 2026 से छात्रों व युवाओं को मदद मिलेगी। इसमें डिजिटल, क्रिएटिव और तकनीकी कौशल सीखने के नए अवसर मिलेंगे। जिले स्तर पर हॉस्टल खुलने से महिलाओं की शिक्षा तक पहुंच बढ़ेगी। रोजगार क्षमताएं और स्टार्टअप सोच को बढ़ावा मिलेगा। छात्रों को नीति-निर्माण प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलेगा। उन्होंने कहा कि केन्द्रीय बजट 2026 में युवा वर्ग के लिए कई प्रावधान किए गए हैं, जो निश्चित रूप से भविष्य में विशेष फायदेमंद साबित होगा। देश भर में 15000 से अधिक सरकारी स्कूलों और 500 कॉलेजों में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित किए जाएंगे। इससे क्रिएटिव और डिजिटल स्किल्स सीखने को प्रोत्साहन मिलेगा।

किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में लाभकारी : कृषक एनेश्वर वर्मा

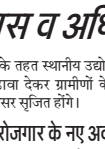

कृषक एनेश्वर वर्मा ने कहा कि किसानों की आमदनी बढ़ाने की दिशा में यह बजट लाभकारी होगा। उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास अंतर्गत पशुपालन क्षेत्र में ऋण आधारित सब्सिडी कार्यक्रम, पशुधन उद्यमों का संवर्धन एवं आधुनिकीकरण, पशुधन उत्पादक संगठनों की स्थापना को प्रोत्साहन देने जैसी पहल के सार्थक परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि कृषि के क्षेत्र में नवीन तकनीक को अपनाने से कार्य सरलता एवं सुगमता से हो रहे हैं। एग्रीस्टेक पोर्टल के माध्यम से कृषकों के बैंक खाता, ऋण, आधार, बैंकिंग एवं अन्य जानकारी डिजिटल फार्म में मिल रही है। इसके साथ ही सब्सिडी की पूरी जानकारी मिल रही है।

उच्च गति वाले रेल कार्रिडोर विकसित होने पर आवागमन में मिलेगी सुविधा : विनय

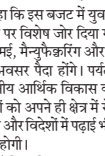

युवा विनय साहू ने कहा कि बजट में 7 उच्च गति वाले रेल कारिडोर विकसित किए जाएंगे। जिससे आवागमन में सुविधा मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए बजट में प्रावधान किए गए हैं। व्यक्तिगत उपयोग के लिए आयात की जाने वाली वस्तुओं पर लगने वाले टैरिफ दर को 20 प्रतिशत से 10 प्रतिशत किया जाएगा। यह एक सराहनीय पहल है।

आयुर्वेद चिकित्सा व ज्ञान को मिलेगा बढ़ावा : डॉ. निलेश गढ़ेवाल

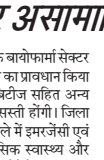

आयुर्वेदिक डॉ. निलेश गढ़ेवाल कहा कि देश में तीन नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित किए जाएंगे। आयुष फार्मेसी एवं औषधि परीक्षण प्रयोगशालाओं का उन्नयन करने, कुशल कार्मिक उपलब्धता कराने और पारंपरिक दवाओं के लिए रिसर्च किया जाएगा, जो सराहनीय है। इससे देश में आयुर्वेद, पारंपरिक योग, आयुर्वेद चिकित्सा एवं ज्ञान को बढ़ावा मिलेगा।

हथकरघा, हस्तशिल्प को मिलेगी मजबूती : चन्द्रकुमार देवांगन

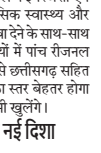

श्री लक्ष्मी बुनकर सहकारी समिति मर्यादित मेढ़ा डोंगरगढ़ के प्रबंधक चन्द्रकुमार देवांगन ने कहा कि बजट में हथकरघा एवं हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रावधान किए गए हैं, जो सराहनीय है। जिसमें मेगा टेक्सटाईल्स पार्क की स्थापना होने से खादी, हथकरघा, हस्तशिल्प को मजबूती मिलेगी और देश के बुनकरों और युवाओं को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि मेगा टेक्सटाईल्स पार्क की स्थापना होने से बुनकरों के हुनर को प्रोत्साहन मिलेगा और उन्हें अपने उत्पाद के लिए एक मार्केट मिलेगा।

महिलाएं होंगी आर्थिक रूप से सक्षम : श्रीमती दिव्या निषाद

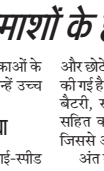

लखपति दीदी श्रीमती दिव्या निषाद ने कहा कि केन्द्रीय बजट में लखपति दीदी कार्यक्रम के लिए बढ़ावा देने हेतु प्रावधान किया गया है और उनके लिए स्वसहायता उद्यम शी मार्ट स्थापित किया जाएगा। जिससे स्वसहायता समूह की महिलाओं को मदद मिलेगा और वे आर्थिक रूप से सक्षम बनेंगी। उन्होंने कहा कि शी मार्ट के माध्यम से समूह की महिलाओं को अपने स्थानीय उत्पादों के लिए मार्केट मिलेगा तथा उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा। जिसके लिए उन्होंने खुशी जाहिर की।

सरकार द्वारा स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना प्रशंसनीय : करण साहू

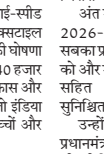

व्यापारी करण साहू ने कहा कि केन्द्रीय बजट में देश के आर्थिक विकास को तेज करने के लिए अच्छी पहल की गई है। उन्होंने कहा कि शहर आर्थिक क्षेत्र विकसित किए जा रहे हैं। जिससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही विकसित भारत के लिए बैंकिंग जैसे प्रावधान से मदद मिलेगी। नए बजट में जनमानस को टीडीएस एवं टीसीएस में राहत मिली है और सरकार द्वारा स्टार्टअप को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जो एक बहुत अच्छी बात है।

केंद्र सरकार बजट विकसित भारत का मजबूत आधार है - मंत्री यादव

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग-भिलाई

दुर्ग। संसद भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमति निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत बजट को लेकर केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने कहा की इस बजट का लाभ हर वर्ग को मिलेगा, सरकार ने आम आदमी के विकास पर फोकस किया है। ये बजट 2047 के विकसित भारत की हमारी ऊंची उड़ान का मजबूत आधार है। आज भारत जिस रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है, इस बजट से उसे नई ऊर्जा, नई गति मिलेगी। पहली बार इस बजट में हथकरघा को लेकर बड़ा बजट प्रावधान किये है, इससे छत्तीसगढ़ प्रदेश में 7 लाख पंजीकृत हथकरघा को लाभ मिलेगा। जिला मुख्यालय के शासकीय अस्पताल को अपग्रेड कर आपातकाल और ट्रामा यूनिट विकसित किया जाएगा जिससे मरीजों को त्वरित उपचार मिलेगा। केबिनेट मंत्री गजेन्द्र यादव ने आगे कहा की पर्यटन के क्षेत्र में 20,000 पर्यटन स्थलों के लिए 10,000 गाइडों का कौशल विकास होगा इससे पर्यटन क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। जन आकांक्षाओं को पूरा करने वाले इस बजट में गंभीर बीमारियों की दवाएं सस्ती होंगी। देश में आयुर्वेद अक्ष्मद्र की स्थापना और भारत के आयुर्वेद के स्तर को आगे बढ़ाने आयुर्वेद उत्पाद को बढ़ावा देने औषधि प्रशिक्षण शाला का निर्माण, निजी क्षेत्र में पशु चिकित्सा को बढ़ावा देने के लिए पूंजी सब्सिडी सहायता योजना लाई जाएगी। पशु-चिकित्सा क्षेत्र में पेशेवरों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। बजट की मुख्य बातों पर उन्होंने आगे बताया की बायोफार्मा सेक्टर में 10 हजार करोड़ का निवेश होगा तथा बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने पर जोर दिया गया है। यह बजट निवेश, उ?द्योग और रोजगार सृजन को मजबूत करेगा। पब्लिक इन्वेस्टमेंट पर फोकस करने के साथ ही मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम पर जोर दिया जाएगा।

केंद्रीय बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है - सरोज पांडेय

भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडेय ने संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश किए गए केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनकर ही संतुष्ट नहीं है। बल्कि जल्द से जल्द तीसरी अर्थव्यवस्था बनना चाहते हैं। ये बजट अपार अवसरों का राजमार्ग है। ये बजट वर्तमान के सपनों को साकार करता है। भारत जिस रिफॉर्म्स पर सवार है, बजट से उसे नई गति मिलेगी।

सुश्री सरोज पांडेय ने आगे कहा कि सनराइज सेक्टर को जिस मजबूती के साथ महत्व दिया है वह अहम है। रेयर अर्थ कॉरिडोर, क्रिटिकल मिनिरल्स पर बल, टैक्सटाइल, हाईटेक टूल मैनुफैक्चरिंग जैसी चीजें भविष्य और वर्तमान की जरूरतों का ध्यान रखती हैं। बजट में इंफ्रा को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। हाई स्पीड रेल कॉरिडोर टियर टू और थ्री शहरों के विकास पर ध्यान ये सारे कदम विकसित भारत की यात्रा की गति को और तेज करेंगे। किसी भी देश की सबसे बड़ी पूंजी नागरिक हैं। हमने इस पर निवेश किया है। हमारा प्रयास स्किल, स्केल और सस्टेनिबिलिटी को मजबूत करने पर रहा है। सुश्री सरोज पांडेय ने आगे कहा कि यह युवा शक्ति बजट है। ऑरेंज इकोनॉमी, पर्यटन और खेलो इंडिया मिशन के जरिए युवाओं के लिए नए अवसरों द्वार खुलेंगे। भारत को दुनिया का डेटा सेंटर हब बनाने टैक्स में बड़ी छूट दी गई है। इस बजट से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को बढ़ावा मिलेगा। हमारे देश में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ी हैं। महिलाओं द्वारा निर्मित संचालित ग्रुप का सिस्टम बने इसका ध्यान बजट में रखा गया है। कोशिश है हर घर लक्ष्मी पहुंचे। हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। अंत में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट छत्तीसगढ़ को विकास की मुख्यधारा में और मजबूती से जोड़ने वाला साबित होगा।

आम जनता को ठगने का दस्तावेज : राकेश ठाकुर

कांग्रेस, जिला दुर्ग के जिलाध्यक्ष राकेश ठाकुर ने केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट रिफॉर्म बजट नहीं बल्कि जनता की पीड़ा से आंख चुराने वाला, कॉर्पोरेट हितों की रक्षा करने वाला और गरीब-विरोधी दस्तावेज है। सरकार ने इस बजट में बड़े-बड़े शब्दों और आकर्षक नारों के पीछे आम नागरिक की समस्याओं को पूरी तरह छिपाने का प्रयास किया है। श्री ठाकुर ने कहा कि देश आज महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और मध्यम वर्ग की टूटती कमर जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा है, लेकिन केंद्र सरकार ने इन मुद्दों पर कोई ठोस समाधान देने के बजाय केवल आंकड़ों और घोषणाओं की बाजीगरी की है। आम जनता को राहत देने के लिए न तो आयकर में कोई वास्तविक छूट दी गई और न ही रोजमर्रा की जरूरतों की महंगाई कम करने के लिए कोई प्रभावी कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि सरकार अब डिजिटल इंडिया और इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर करोड़ों रुपये के प्रावधान दिखा रही है, लेकिन यह पूरी तरह रोजगारविहीन विकास मॉडल है। युवाओं के लिए न तो स्थायी नौकरियों की व्यवस्था की गई और न ही बंद पड़ी सरकारी भर्तियों को शुरू करने की कोई मंशा दिखाई दी। आज देश का युवा डिग्री लेकर सड़कों पर भटक रहा है और सरकार केवल भविष्य के सपनों की बातें कर रही है। राकेश ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़, ओडिशा और केरल में माइनिंग कॉरिडोर की घोषणा यह साबित करती है कि भाजपा सरकार का असली एजेंडा प्राकृतिक संसाधनों को कॉर्पोरेट कंपनियों के हवाले करना है। इससे आदिवासी क्षेत्रों में विस्थापन बढ़ेगा, पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचेगी और स्थानीय लोगों के अधिकारों का हनन होगा। कांग्रेस इस लूट के खिलाफ मजबूती से खड़ी है।

देशवासियों की भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप यह बजट-विजय बघेल

दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए इसे ऐतिहासिक एवं जन-आकांक्षाओं के अनुरूप बजट बताया। विजय बघेल ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण ने 140 करोड़ देशवासियों की भावनाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप यह बजट प्रस्तुत किया है। यह बजट समाज के प्रत्येक वर्ग—युवा, किसान, महिला, श्रमिक, मध्यम वर्ग सहित कलाकारों और साहित्यकारों—को सशक्त करने वाला है।

उन्होंने कहा कि वित्त मंत्री के नाम के अनुरूप यह बजट निर्मल, ममतामयी एवं रमणीय है, जिसमें सामाजिक संवेदनशीलता और विकास का संतुलन स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। यह बजट आत्मनिर्भर भारत के विजन को और मजबूती प्रदान करता है। सांसद विजय बघेल ने बताया कि बजट में सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सेवा क्षेत्र सहित विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही आयकर से जुड़े नए प्रावधानों से आम नागरिकों को राहत मिलने की उम्मीद है। आगे कहा की उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं अपनी ओर से समस्त देशवासियों को इस जनहितैषी बजट के लिए हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं।

बजट देश के 140 करोड़ लोगों की जन भावनाओं का प्रतीक - सौरभ जयसवाल

भारतीय जानता पार्टी युवा मोर्चा जिला भिलाई के अध्यक्ष सौरभ जयसवाल ने वित्त मंत्री निमर्ला सीतारमण के द्वारा पेश किए गए बजट की तारीफ करते हुए कहा कि मोदी सरकार का यह बजट देश के 140 करोड़ लोगों की जन भावनाओं का प्रतीक है। इस बजट में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास का मूल मंत्र है। देश की बुनियादी ढांचे को मजबूत करने वाला, रोजगार प्रदान करने वाला और विकसित भारत के नीव को मजबूत करने वाला बजट है।

कौशल, तकनीक और रोजगार से विकसित भारत की मजबूत नींव– मंत्री गुरु खुशवंत साहेब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में तथा केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत के संकल्प को साकार करने वाला एक ऐतिहासिक एवं दूरदर्शी दस्तावेज है। इस बजट पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि यह बजट युवाओं को कौशल, तकनीक और रोजगार से जोड़ते हुए आत्मनिर्भर भारत की मजबूत आधारशिला रखता है। उन्होंने कहा कि कर्तव्य भवन में प्रस्तुत यह पहला बजट है, जिसमें आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सबका साथ, सबका विकास की भावना को केंद्र में रखा गया है। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और श्रमिक वर्ग के सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगा, जिसका सीधा लाभ छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को मिलेगा।

मंत्री श्री साहेब ने कहा कि बजट में युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार को विशेष प्राथमिकता दी गई है। स्टार्टअप, एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन एवं सेवा क्षेत्रों में नए रोजगार अवसर सृजित होंगे। तकनीकी शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और इंडस्ट्री-लिंक्ड ट्रेनिंग से युवा भविष्य-उन्मुख कौशल से लैस होंगे। उन्होंने कहा कि एआई, आधुनिक तकनीक और नवाचार को बढ़ावा देकर कार्यबल को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के अनुरूप तैयार करने की ठोस पहल की गईहै, जिससे आईटीआई, पॉलिटेक्निक और प्रशिक्षण संस्थानों को नई दिशा मिलेगी। कृषि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र, महिला सशक्तिकरण तथा औद्योगिक विकास से जुड़ी घोषणाएं बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करेंगी। अंत में मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास की भावना को और सुदृढ़ करता है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की जनता की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक अवश्य पहुंचाएगा।

युवा शक्ति, अन्नदाता व बुनियादी ढांचे को समर्पित विकसित भारत निर्माण का सशक्त ब्लूप्रिंट है बजट - रिकेश सेन

केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया केंद्रीय बजट केवल एक वित्तीय विवरण नहीं, बल्कि 'विकसित भारत' के निर्माण का एक सशक्त ब्लूप्रिंट है। जहां विपक्ष केवल भ्रम फैलाता है वहीं मोदी सरकार ने वित्तीय घाटे को 4 .3 प्रतिशत पर सीमित रख कर यह दिखा दिया है कि आर्थिक अनुशासन और जन-कल्याण साथ-साथ चल सकते हैं। जहां एक ओर यह बजट नकारात्मक राजनीति के मुंह पर तमाचा है वहीं युवा शक्ति, अन्नदाता और बुनियादी ढांचे को समर्पित भी है।

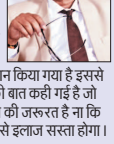

श्री सेन ने कहा कि यह बजट अंत्योदय के मंत्र को साकार करते हुए समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने वाला है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 12 .2 लाख करोड़ का प्रावधान किया है, जो देश के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा निवेश है। इससे न केवल सड़कें और पुल बनेंगे, बल्कि लाखों नए रोजगार भी सृजित होंगे। कृषि क्षेत्र में डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन और 500 जलाशयों के एकीकृत विकास की घोषणा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी। बायो फार्मा शक्ति योजना, कैंसर की 17 दवाओं पर कस्टम ड्यूटी हटाना मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत है। आयकर की नई व्यवस्था में 12 .75 लाख तक की आय को कर मुक्त रखने और स्टेंडर्ड डिडक्शन के लाभों को निरंतर रखना मध्यम वर्ग की बचत बढ़ाने वाला कदम है। हाई स्पीड रेल और कनेक्टिविटी से यात्रा का समय कम होगा और व्यापार बढ़ेगा। डेढ़ लाख मल्टी-स्किल्ड केयरगिवर्स को प्रशिक्षित करने और 15 हजार स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित करने का निर्णय भविष्य की पीढ़ी को तैयार करने वाला है।

विकसित भारत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम-डॉ . सलीम राज

केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष एवं कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त डॉ . सलीम राज ने सराहनीय बताते हुए इसे विकसित भारत का बजट कहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तैयार यह बजट देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। डॉ . राज ने कहा कि इस बजट में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 3400 करोड़ रुपये कर दिया गया है, जो पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि दर्शाता है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान अल्पसंख्यक समुदायों के सामाजिक-आर्थिक उत्थान, शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को सुदृढ़ करने में सहायक होगा। उन्होंने कहा कि यह बजट समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। किसानों, युवाओं, महिलाओं, श्रमिकों और मध्यम वर्ग के साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदायों के लिए भी इसमें ठोस योजनाएँ शामिल हैं। शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में किए गए प्रावधान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त बनाएंगे, वहीं रोजगार और उद्यमिता को बढ़ावा देने वाली योजनाएँ आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को मजबूत करेंगी। डॉ . राज ने कहा कि यह बजट केवल वित्तीय घोषणाओं का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह विकसित भारत 2047 के संकल्प को साकार करने वाला दूरदर्शी और जन-कल्याणकारी दृष्टिकोण है। प्रधानमंत्री जी और वित्तमंत्री ने जिस तरह से हर वर्ग को ध्यान में रखकर योजनाएँ प्रस्तुत की हैं, वह सुशासन और संवेदनशील नेतृत्व का प्रमाण है।

रोजगार और संरचना, विनिर्माण विकसित करने वाला बजट-वित्त मंत्री

चुनौतियों और अनिश्चितताओं के समय में वित्त मंत्री के लिए बजट बनाना है इतना आसान नहीं था। वित्त मंत्री ने वृद्धि को सतत रूप से बनाए रखने के लिए संरचनात्मक सुधारों के माध्यम से आधारभूत संरचना, विनिर्माण और रोजगार की क्षमता को विकसित करने वाले आधार को मजबूत किया है। लगभग 53 .47 लाख करोड़ के बजट में राजकोषीय अनुशासन को बनाए रखते हुए एक ओर राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4 .3 प्रतिशत पर रखा है वहीं ऋण को जीडीपी के 55 .6 प्रतिशत पर रखने का लक्ष्य रखा है। वित्त मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य आकांक्षा को उपलब्धि में और क्षमता को निष्पादन में परिवर्तित करना है और यह सुनिश्चित करना है कि विकास का लाभ हर किसी तक पहुंचे। बजट में सबसे अधिक प्रावधान आधारभूत संरचना के लिए 12 .02 लाख करोड़ का रखा गया है। साथ ही रणनीतिक और फ्रंटियर क्षेत्र के विनिर्माण उद्योगों के लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं। विनिर्माण उद्योग के लिए अनेक कर सुधार भी बजट में है। मध्य और लघु उद्योगों को इक्विटी सपोर्ट एक महत्वपूर्ण कदम है। देश की अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र का जीडीपी निर्यात और रोजगार में महत्वपूर्ण योगदान है। । इसी को देखते हुए टूरिज्म, स्वास्थ्य, शिक्षा और वित्तीय क्षेत्र के लिए अनेक अभिनव प्रावधान बजट में किए गए हैं।

बजट 2026-27 गांव से शहर तक विकास का स्वर्णिम अध्याय लिखने वाला है -जितेन्द्र वर्मा

केंद्र सरकार ने संसद के लोकसभा सत्र में सदन के पटल पर वर्ष 2026-27 का बजट रखा हैं। केंद्रीय बजट 2026-27 का स्वागत करते हुए भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी मार्गदर्शन में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण द्वारा संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 राष्ट्र के सर्वांगीण विकास की दिशा में एक मजबूत और निर्णायक कदम है।

भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने कहा कि यह पहला बजट है, जो कर्तव्य भवन में बना है। इस बजट के तीन प्रमुख कर्तव्य हैं - आर्थिक ग्रोथ को बढ़ावा देना, जनता की उम्मीदों को पूरा करना, सबका साथ, सबका विकास। भाजपा प्रदेश मंत्री जितेन्द्र वर्मा ने आगे कहा कि यह बजट विकसित भारत 2047 के संकल्प को पूर्ण करने की स्पष्ट रूपरेखा प्रस्तुत करता है, जिसमें गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग, व्यापारी, श्रमिक एवं उद्यमियों सभी वर्गों व क्षेत्रों के हितों का समावेश किया गया है। इस बजट में कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, अधोसंरचना, रोजगार सृजन, स्टार्टअप, एमएसएमई, डिजिटल इंडिया एवं आत्मनिर्भर भारत को नई गति देने वाले प्रावधान किए गए हैं।

इलेक्ट्रॉनिक कम्पोनेंट विनिर्माण योजना के लिए परिव्यय बढ़कर 40,000 करोड़ रुपये हो जाएंगे, खादी,हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ किया जाएगा, प्राकृतिक, मानव निर्मित और न्यू ऐज फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना, लघु, मध्यम उद्यमों को चैंपियन बनाना और सूक्ष्म उद्यमों को सहायता प्रदान करने की योजना, कार्बन कैप्चर उपयोग और संग्रहण (सीसीयूएस) के लिए अगले पांच वर्षों में 20,000 करोड़ रुपये के परिव्यय का प्रस्ताव, दिव्यांगजन कौशल योजना, दिव्यांजन सहारा योजना, ग्रामीण महिलाओं के नेतृत्व वाले उद्यम के लिए SHE-मार्टस, बहु भाषीय एआई टूल, 500 जलाशयों और अमृत सरोवरों के एकीकृत विकास, 2047 तक भारत को सेवा क्षेत्र में 10% वैश्विक हिस्सेदारी के साथ ग्लोबल लीडर बनाना, 1,000 करोड़ से अधिक लागत के एकल बॉन्ड इश्यू करने के लिए 100 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि, आईटी सेवाओं में सुरक्षित हार्बर प्राप्त करने के लिए लागत मूल्य को 300 करोड़ से 2000 करोड़ करने का प्रस्ताव, तेंदूपत्ता उद्योग से जुड़े लोगों के लिए TCS की दर 5% घटाकर सिर्फ 2% की गई है।

युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम -मनीष पाण्डेय

भिलाई नगर। केंद्रीय वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत का बजट बताते हुए श्रीराम जन्मोत्सव समिति के युवा विंग अध्यक्ष एवं भाजपा नेता मनीष पाण्डेय ने इसका स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में तैयार यह बजट युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने और उन्हें नए अवसर प्रदान करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम है।

श्री पाण्डेय ने कहा कि यह बजट रोजगार सृजन, कौशल विकास, शिक्षा से रोजगार तक की कड़ी को मजबूत करने और उद्यमिता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान केंद्रित करता है। शिक्षा से रोजगार कमेटी का गठन युवाओं को शिक्षा से लेकर उद्योग जगत और रोजगार तक जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा। इससे युवाओं को न केवल रोजगार मिलेगा बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर भी प्राप्त होगा। श्री पाण्डेय ने कहा कि खेल के क्षेत्र में भी बजट ने नई ऊर्जा का संचार किया है। युवा एवं खेल मंत्रालय का बजट बढ़ाकर 45,000 करोड़ से अधिक कर दिया गया है, जिससे खेलो इंडिया जैसी योजनाओं को अगले दस वर्षों तक और मजबूती मिलेगी। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में खेल अवसंरचना का विस्तार होगा, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर प्रशिक्षण और सुविधाएँ प्राप्त होंगी। साथ ही, खेल उपकरण निर्माण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष पहल की गई है, जिससे भारत उच्च गुणवत्ता वाले खेल उपकरणों का वैश्विक केंद्र बन सकेगा।

केंद्रीय बजट काफी नपा तुला और सामान्य - प्रदेशाध्यक्ष देवेश मिश्रा

दुर्ग - सनातन धर्म सेवा परिषद भारत के राष्ट्रीय प्रमुख एवं भारतीय गण वार्ता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेश मिश्रा ने केंद्रीय मंत्री निमर्ला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट को काफी नपा तुला और सामान्य बजट बताया है। विदेश में पढ़ाई और इलाज खर्च पर राहत देते हुए विदेशी शिक्षा और चिकित्सा के लिए ळउर रेट 5% से घटाकर 2% किया जाना एक अच्छा कदम है। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर लगभग 12 .2 लाख करोड़ के खर्च का प्रस्ताव एवं इंफ्रा रिस्क गारंटी फण्ड के गठन की घोषणा स्वागतेय है, जिससे बड़े प्रोजेक्ट्स में निवेश का जोखिम कम हो। इसके अलावा हर जिले में एक गर्ल्स हॉस्टल की योजना, रटए और टरटए सेक्टर के लिए नई क्रेडिट गारंटी सपोर्ट स्कीम लाने से छोटे कारोबारियों को उद्योग हेतु कर्ज लेना आसान होगा, जो कि एक अच्छा कदम है।

एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान पर्याप्त नहीं : केके झा

एमएसएमई जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष के . के . झा ने केंद्रीय बजट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि एमएसएमई के लिए 10 हजार करोड़ का प्रावधान किया गया है जो की पर्याप्त नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा। इसे कम से कम 1 लाख करोड़ बढ़ाए जाने की जरूरत है। बजट में इंपोर्ट को बढ़ावा देने की बात कही गई है जबकि एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना था। एक्सपोर्ट बढ़ने से ही एमएसएमई का विकास होगा। एमएसएमई रोजगार का एक बड़ा सेक्टर है इससे रोजगार के अवसर पढ़ेंगे। उन्होंने कहा कि बजट में एजुकेशन सेक्टर को छोड़ दिया गया है, खासकर प्राइमरी एजुकेशन को बढ़ावा देना था। देश के रक्षा बजट में 15 .2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को स्वागतेय बताते हुए उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स समय पर नहीं देने पर पूर्व में जेल का प्रावधान था लेकिन वतर्मान बजट में फाइन का प्रावधान किया गया है इससे शासन को टैक्स में बढ़ोतरी होगी, वहीं लोगों के स्वाभिमान की रक्षा भी होगी। बजट में इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात कही गई है जो सिर्फ घोषणा ही साबित होती है। शहरों के लिए 5 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है इसे लागू करने की जरूरत है ना कि सिर्फ घोषणा करने की।कैंसर और डायबिटीज की दवा पर कस्टम ड्यूटी हटाने की बात कही गई है इससे इलाज सस्ता होगा।

गांव, गरीब व किसान व मध्यमवर्गीय विरोधी बजट - पिंटू

राजनंदगांव। केंद्र के मोदी सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता कमलजीत पिंटू ने बजट प्रतिक्रिया में कहा है कि देश के वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट गांव, गरीब ,किसान एवं मध्यवर्गीय विरोधी बजट है पूर्व में मनरेगा के तहत गांव एवं गरीब किसान के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए 90% अंश केंद्र सरकार एवं 10% अंश राज्य को वहन करना होता था लेकिन अब मोदी सरकार द्वारा मनरेगा का नाम बदलकर वीबीजी राम जी करके केंद्र का भार घटाकर 60% एवं राज्य का भार बढ़ाकर 40% खर्च करने का प्रावधान होने से छत्तीसगढ़ को इसका लाभ मिलना मुश्किल होगा क्योंकि छत्तीसगढ़ का भाजपा सरकार आर्थिक रूप से छत्तीसगढ़ को बदहाल कर दिया है , किसानों के उपज का कीमत बढ़ने का कोई प्रावधान बजट में नहीं है, बेरोजगारों के लिए रोजगार देने का कोई पर्याप्त प्रावधान नहीं है, छोटे एवं मध्यवर्गीय व्यापारी जीएसटी में कमी होगी ऐसा अनुमान लगाए थे लेकिन उनके उम्मीद में पानी फिरा, बजट से दैनिक उपयोग की आवश्यक सामानों पर महंगाई में कोई कमी नहीं होगी बल्कि महंगाई में भारी बढ़ोतरी होगी केंद्रीय बजट आम लोगों की उम्मीदों के विरुद्ध है, केंद्रीय बजट केवल पूंजीपतियों को ध्यान में रख कर ही तैयार किया गया है, गरीब मध्यम वर्ग को कोई लाभ नहीं मिलेगा, केवल हवा हवाई बजट है।

जनकल्याण, विकास और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में मजबूत कदम — कीर्ति नायक

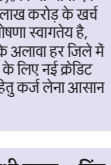

पाटन। जनपद पंचायत पाटन की अध्यक्ष श्रीमती कीर्ति नायक ने आज प्रस्तुत केंद्रीय बजट का स्वागत करते हुए इसे जनहित, ग्रामीण विकास और आत्मनिर्भर भारत की सोच को सशक्त करने वाला बजट बताया है। श्रीमती नायक ने कहा कि यह बजट किसानों, महिलाओं, युवाओं, गरीब एवं मध्यम वर्ग के लिए आशा और विश्वास का बजट है। ग्रामीण आधारभूत ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार सृजन और स्वरोजगार को प्राथमिकता देकर केंद्र सरकार ने देश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुँचाने का स्पष्ट संदेश दिया है।

उन्होंने कहा कि बजट में ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, पंचायत सशक्तिकरण, अधोसंरचना निर्माण और युवाओं के लिए कौशल विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे गांवों में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और पलायन पर रोक लगेगी। जनपद अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में प्रस्तुत यह बजट विकसित भारत के संकल्प को मजबूती देता है। यह बजट आर्थिक स्थिरता के साथ-साथ सामाजिक न्याय और समावेशी विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। श्रीमती कीर्ति नायक ने विश्वास व्यक्त किया कि केंद्रीय बजट के प्रावधानों का लाभ छत्तीसगढ़ सहित पाटन जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुँचेगा और इससे क्षेत्र के समग्र विकास को नई गति मिलेगी।

किसान,गरीब, युवा हर कोई इस बजट से बेहद प्रसन्न - विनय सेन

भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला महामंत्री विनय सेन ने केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण के प्रस्तुत केंद्र सरकार की बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि केंद्र की यह बजट राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाने वाली बजट है। यह बजट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदृष्टि का महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जिसे केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निमर्ला सीतारमण ने देश के सदन के पटल पर रखा है ।यह बजट 3ऊको समर्पित है अर्थात डी फॉर - डेवलपमेंट, डी फॉर - डिमांड, डी फॉर - डिजिटाइजेशन डेवलपमेंट के माध्यम से विकसित भारत की संकल्पना को पूरा करना। डिमांड से समाज में समग्र पूर्ति की बातें और डिजिटलाइजेशन से समाज में नए भारत और विकसित भारत के संकल्प को पूर्ण करने का फैसला लिया गया है। बजट में हर वर्ग की इसमें चिंता की गई है ।किसान,गरीब, युवा हर कोई इस बजट से बेहद प्रसन्न है ।केंद्रीय बजट में 12 लाख रुपए तक की आय पर कोई कर नहीं लगेगा यह निर्णय मध्यम वर्ग के लिए बड़ी राहत की बात है। इससे आर्थिक विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा सकता है।

संपादकीय

राजनीति की गुंजाइश तो हमेशा रहती है

किसी भी राज्य में कोई भी सरकार कोई भी ऐसा काम तो कर नहीं सकती कि उस पर विपक्षी दल राजनीति ही न कर सके। कहीं न कहीं कुछ छूट जाता है, कहीं न कहीं कोई कमी रह जाती है। ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है कि वह कोई काम पूरा न करे व कोशिश तो करती है कि तय समय के भीतर वह जो चाहती है, वह हो जाए लेकिन कई कारणों से ऐसा हो नहीं पाता है जिसे सरकार भले ही अपनी असफलता न माने लेकिन विपक्षी दल तो उसे सरकार की असफलता मानेगा भी और उस पर राजनीति करेगा भी कि सरकार ने जो कहा था वह कर नहीं पाई। विपक्ष तो दावा करेगा ही कि वह जैसा कह रहा था, वैसा ही हुआ है। सरकार ने कहा था कि वह किसानों का पूरा धान खरीदेगी, वहीं विपक्ष ने कहा था सरकार किसानों का पूरा धान खरीदना ही नहीं चाहती है।

राज्य मे साय सरकार ने किसानो का धान समर्थन मूल्य पर खरीदने के लिए पूरे राज्य पिछली बार से ज्यादा अच्छी तैयारी की थी क्योंकि हर बार सरकार की कोशिश यही रहती है कि ज्यादा किसानों का धान पिछली बार से ज्यादा खरीदा जाए। किसानों को धान बेचने में कोई परेशानी न हो, उनको टोकन में कोई परेशानी न हो, उनको धान का भुगतान होने में कोई दिक्कत न हो। फिर भी किसानों को धान बेचने में कोई न कोई परेशानी हो जाती है, बहुत सारे किसान समय पर धान बेच नहीं पाते हैं। इस बार भी यही हुआ है जितने किसानों ने पंजीयन कराया था, उनमें से खबरों के मुताबिक ढाई लाख किसान धान नहीं बेच पाए हैं ।आंकड़ों के मुताबिक इस बार धान बेचने के लिए २७ लाख से ज्यादा किसानों ने पंजीयन कराया था जिसमें से २५ लाख किसान धान बेच चुके है तथा ढाई लाख किसान धान बेचने के लिए टोकन नहीं कटा पाए हैं।

सरकार किसानों का धान खरीदने के लिए सीमा तय कर देती है कि इस दिन से धान खरीदी शुरू होगी और इस दिन तक होगी। इस दौरान सभी किसानों को अपना धान बेचना होता है,सरकार पहले से धान खरीदी का लक्ष्य तय कर देती है। ऐसा इसलिए करती है ताकि ज्यादा किसानों का ज्यादा धान खरीदा जा सके। पिछले साल सरकार ने किसानों से १४९ लाख टन धान खरीदा था इस बार तय दिन तक १३९ लाख टन धान की खरीदी हो सकी है ।टन में तो ऐसा लगता है कि सरकार ने पिछली बार से १० लाख टन धान कम खरीदा है लेकिन जब प्रतिशत की बात आती है तो आंकड़ों से पता चलता है कि पिछली बार सरकार ने कुल पंजीयन कराने वाले किसानों में ९१ प्रतिशत किसानों का धान खरीदा था जबकि इस बार जितने किसानों ने पंजीयन कराया है उसमे से ९२ प्रतिशत किसानों का धान सरकार ने खरीदा है यानी सरकार कह सकती है कि उसने तो पिछली बार से ज्यादा किसानों से धान खरीदा है, यह सच है लेकिन विपक्ष को तो कहने का मौका मिलेगा कि सरकार ने सभी किसानों का धान नहीं खरीदा है।

यह सच है कि जितने किसानों ने पंजीयन कराया था, उसमें से ज्यादा से ज्यादा किसानों का धान सरकार ने खरीदने का प्रयास किया है लेकिन फिर भी आए दिन खबरें तो आती रही है कि किसानों को टोकने कटाने में परेशानी हो रही है, धान नहीं बेच पाने पर कुछ किसानों ने आत्महत्या का प्रयास भी किया है, किसानों ने कई बार चक्का जाम भी किया है। किसानों की परेशानी को देखते हुए कांग्रेस ने सरकार से धान खरीदी खत्म होने के पहले से मांग की थी बहुत सारे किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं, इसलिए सरकार को एक माह या पंद्रह दिन धान खरीदने का समय बढ़ाना चाहिए। धान खरीदी खत्म हो चुकी है, यह साफ भी हो गया है कि बहुत सारे किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं फिर भी सरकार की तरफ से अभी तक तो कहा नही गया है कि सरकार बचे किसानों का धान खरीदने के लिए समय बढ़ाएगी। माना जा रहा है कि सरकार ने जितना धान खरीद लिया है, वह उसे पर्याप्त मानती है और अब और धान नही खरीदना चाहती। पिछली बार ज्यादा धान खरीदने के कारण सरकार को बाद में धान कम दाम पर बेचना पड़ा था और सरकार को इससे घाटा हुआ था हो सकता है कि सरकार ने पिछली बार के घाटे को देखते हुए इस बार तय समय तक जितना धान खरीदा जा सका है उसे बहुत मानती है। इस बार वह ज्यादा धान खरीद कर धान खरीदी में घाटा नहीं उठाना चाहती है।

सरकार कितना भी धान खरीदे यदि कांग्रेस यह तो देखेगी नही कि सरकार कितना धान किसानों से खरीदा है वह तो यह देखेगी कि सरकार ने कहा था कि वह किसानों का पूरा धान ख ?ीदेगी कितने किसानों का धान सरकार ने नहीं खरीदा है यानी कांग्रेस के लिए यह अहम बात है कि कितने किसान अपना धान नहीं बेच पाए हैं वह तो सरकार से पहले से मांग कर रही हैं कि बहुत सारे किसान धान नहीं बेच पाए इसलिए उनका धान खरीदने के लिए सरकार धान खरीदने का समय बढ़ाए ।सरकार किसी भी कारण से समय नहीं बढ़ाती है तो कांग्रेस तो सरकार पर आरोप लगाएगी ही कि उसने वादा करके किसानों का पूरा धान नहीं खरीदा ।छत्तीसगढ़ की राजनीति में किसानों का समर्थन व नाराजगी बहुत मायने रखती है। जिससे किसान खुश वह सरकार सफल मानी जाती है जिससे किसान नाराज वह सरकार असफल मानी जाती है।

तेल के खेल में मोदी के आगे कोई नहीं टिक सकता
भारत-वेनेजुएला वार्ता के बाद दुनिया में मची हलचल

नीरज कुमार दुबे

भारत और वेनेजुएला के बीच कूटनीति ने अचानक तेज रफ्तार पकड़ ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच हुई टेलीफोन वार्ता ने वैश्विक ऊर्जा राजनीति में जबरदस्त हलचल पैदा कर दी है। माना जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच हुई इस वार्ता का सीधा संबंध तेल से है और इसका परोक्ष असर भारत रूस निर्भरता घटाने, अमेरिका से व्यापारिक दबाव कम करने और ग्लोबल साउथ में भारत की रणनीतिक स्थिति मजबूत करने से जुड़ा है।

सूत्रों के अनुसार अमेरिका ने भारत को संकेत दिया है कि वह शीघ्र ही वेनेजुएला से तेल खरीद दोबारा शुरू कर सकता है ताकि रूसी कच्चे तेल पर निर्भरता घटे। यह पहल भारत अमेरिका ऊर्जा संबंधों को नए सांचे में ढालने की अमेरिकी कोशिश का हिस्सा है। रिपोर्टों के मुताबिक आने वाले महीनों में भारत रूसी तेल आयात में प्रतिदिन कई लाख बैरल की कटौती कर सकता है। इस कूटनीतिक पृष्ठभूमि में डेल्सी रोड्रिगेज ने प्रधानमंत्री मोदी से वार्ता के बाद ऊर्जा सहयोग पर सहमति की पुष्टि की। प्रधानमंत्री ने भी सार्वजनिक संदेश में कहा कि दोनों देश द्विपक्षीय साझेदारी को सभी क्षेत्रों में नई ऊंचाइयों तक ले जाने की साझा दृष्टि रखते हैं। हम आपको बता दें कि यह वार्ता ऐसे समय हुई है जब वेनेजुएला ने अपने हाइड्रोकार्बन क्षेत्र को निजी कंपनियों के लिए खोलने का ऐतिहासिक फैसला लिया है।

वेनेजुएला दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडारों वाला देश है। दशकों तक कठोर सरकारी नियंत्रण के बाद अब कानूनों में व्यापक सुधार किए गए हैं। खोज, उत्पादन, वितरण और विपणन में निजी भागीदारी को अनुमति दी गई है। कर और रॉयल्टी घटाई गई हैं, बड़े प्रोजेक्ट के लिए शुल्क और कम किए जा सकते हैं और विवादों में अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता का रास्ता खोला गया है। इस तरह यह बदलाव कर पूर्व राष्ट्रपति ह्यूगो चावेज के दौर की राष्ट्रीयकरण नीति को पलट दिया गया है।

अमेरिका ने भी जवाबी कदम उठाते हुए वेनेजुएला को प्रतिबंधों में ढील दी है। नया सामान्य लाइसेंस अमेरिकी कंपनियों को वेनेजुएला के तेल के निर्यात, भंडारण, परिवहन और परिशोधन की अनुमति देता है, हालांकि भुगतान और कुछ देशों से जुड़े लेन-देन पर सख्त शर्तें रखी गई हैं। हम आपको याद दिला दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल मार्च में वेनेजुएला से तेल खरीदने वाले देशों पर भारी शुल्क लगाया था, जिसमें भारत भी शामिल था। अब दिशा बदली है।

देखा जाये तो रूस यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने अवसर का लाभ उठाते हुए सस्ता रूसी तेल बड़ी मात्रा में खरीदा। इससे देश की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी हुईं और कीमतों पर भी नियंत्रण रहा। लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। अमेरिका का दबाव बढ़ा है, व्यापार शुल्क भारी हुए हैं और प्रतिबंधों के कारण आपूर्ति व्यवस्था जटिल हो गई है। इसी वजह से भारत अब तेल आयात के नए विकल्प तलाश रहा है। आयात के ताजा आंकड़े बताते हैं कि दिसंबर में रूस से तेल खरीद दो साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। इसके साथ ही ओपेक देशों से आने वाले तेल की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ी है। कई भारतीय रिफाइनरियों ने रूसी कच्चे तेल से दूरी बना ली है और आपूर्ति स्रोत बदलने शुरू कर दिए हैं।

इसी बीच, वेनेजुएला के नए कानून ने एक नई संभावना खोली है। उत्पादन और निर्यात में तेज बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिबंधों के चलते जो तेल पहले मजबूरी में सस्ते दाम पर बेचना पड़ता था, अब वह बेहतर कीमत और कम लागत के साथ खुले बाजार में उपलब्ध होगा। सरकारी आकलन के अनुसार, वेनेजुएला में इस साल उत्पादन में 18 प्रतिशत तक बढ़ोतरी संभव है, जबकि निजी अनुमान इससे भी तेज उछाल की ओर संकेत कर रहे हैं।

देखा जाये तो मोदी और रोड्रिगेज की बातचीत सिर्फ एक शिष्टाचार नहीं, बल्कि सामरिक संकेत है। भारत साफ तौर पर संदेश दे रहा है कि वह किसी एक स्रोत या किसी एक धड़े के साथ नहीं रहेगा। ऊर्जा सुरक्षा भारत की आर्थिक संप्रभुता की रीढ़ है और इस रीढ़ को मजबूत करने के लिए बहुध्रुवीय नीति अनिवार्य है। वेनेजुएला के दरवाजे खुलना भारत के लिए अवसर की तरह है क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार तक पहुंच सस्ती और स्थिर आपूर्ति का रास्ता खोल सकती है। हालांकि भारत को अमेरिकी शर्तों, भुगतान नियमों और भू-राजनीति की रस्साकशी में संतुलन भी साधना होगा।

सामरिक रूप से यह कदम रूस पर निर्भरता घटाकर भारत की सौदेबाजी की शक्ति को और बढ़ाता है। यदि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद फिर शुरू करता है तो अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव कम हो सकता है, साथ ही लैटिन अमेरिका में भारत की मौजूदगी मजबूत होगी। ग्लोबल साउथ के मंच पर भी यह संकेत जाएगा कि भारत ठोस साझेदारी करता है। वहीं वेनेजुएला ने नियम सरल कर यह दिखा दिया है कि आर्थिक यथार्थ विचारधारात्मक जिद से बड़ा होता है। निजी निवेश, कम कर, अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता और पारदर्शिता से ही उत्पादन बढ़ेगा और आम नागरिक तक लाभ पहुंचेगा। भारत यदि यहां निवेश और दीर्घकालिक खरीद समझौते करता है तो यह दोनों देशों के लिए लाभकारी होगा।

बहरहाल, इस पूरी तस्वीर के केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल और दूरदर्शी विदेश नीति साफ दिखाई देती है। कच्चे तेल की खरीद और आपूर्ति के मोर्चे पर उन्होंने खुद को एक मास्टर रणनीतिकार के रूप में स्थापित किया है। जब दुनिया रूस यूक्रेन युद्ध के बाद तेल संकट से जूझ रही थी, तब भारत पर भी हर तरफ से दबाव था कि वह सस्ते रूसी तेल से दूरी बनाए। इसके बावजूद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय हित को सर्वोपरि रखते हुए बहुस्तरीय कूटनीति अपनाई। रूस से तेल खरीद जारी रखी, पश्चिम एशिया और अफ्रीका से आपूर्ति संतुलित की और अब लैटिन अमेरिका की ओर रणनीतिक कदम बढ़ा दिये हैं। इसी संतुलित नीति का नतीजा रहा कि जहां यूरोप और अमेरिका में ईंधन के दाम आसमान छू रहे थे, वहीं भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें काबू में रहीं। यह केवल आर्थिक प्रबंधन नहीं था, बल्कि वैश्विक दबावों के बीच भारत की सामरिक स्वायत्तता और नेतृत्व क्षमता का स्पष्ट प्रदर्शन था। देखा जाये तो मौजूदा संकेत साफ बता रहे हैं कि नई दिल्ली लगातार कुशल रणनीति के साथ फैसले कर रही है। यही आक्रामक यथार्थवाद आज के दौर की मांग है।

केंद्र के अनुरोध

सुप्रीम कोर्ट के जज न्यायमूर्ति उज्जल भूइंया ने यह सटीक प्रश्न उठाया है कि किसी जज का एक से दूसरे हाई कोर्ट में सिर्फ इसलिए क्यों तबादला होना चाहिए कि उसने सरकार के लिए कोई 'असुविधाजनक निर्णयइ दिया हो?

जब संभल के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विभांशु सुधीर का विवादित तबादला चर्चा में है, सुप्रीम कोर्ट ने जज उज्जल भूइंया ने उच्चतर न्यायपालिका के जजों के तबादले के पीछे की राजनीतिक कहानी पर से परदा हटा कर काफी कुछ उजाले में ला दिया है। न्यायमूर्ति भूइंया ने पूछा कि किसी जज का एक से दूसरे हाई कोर्ट में सिर्फ इसलिए क्यों तबादला होना चाहिए कि उसने सरकार के लिए कोई 'असुविधाजनक निर्णयइ दिया हो? हालांकि न्यायमूर्ति ने कोई नाम नहीं लिया, लेकिन अनुमान लगाया गया है कि उनका इशारा बीते अक्टूबर में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जज अतुल श्रीधरन के तबादले की ओर था।

जस्टिस श्रीधरन ने कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में मध्य प्रदेश के एक मंत्री के बयान का संज्ञान लिया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने पहले उनका तबादला छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट किया, लेकिन तुरंत ये फैसला बदल कर उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया। अब साफ है कि ऐसा केंद्र के अनुरोध पर किया गया। आम चर्चा है कि इस रूप में सरकार कॉलेजियम के तबादला संबंधी कई फैसलों के प्रभावित कर चुकी है। और जब उच्चतर न्यायपालिका में ये हाल हो, तो निचली अदालतों के बारे में सहज अनुमान लगाया जा सकता है। सीजेएम सुधीर ने संभल की हिंसा के मामले में पुलिस अधिकारी पर मामला दर्ज करने का निर्देश दिया। उसके कुछ ही दिन बाद उनका तबादला हो गया।

जस्टिस भूइयां ने उचित चेतावनी दी है कि ऐसी घटनाएं भारतीय न्यायपालिका की साख पर बट्टा लगा रही हैं। उन्होंने कहा- 'अगर हमने अपनी साख खो दी, तो न्यायपालिका में कुछ नहीं बचेगा। जज रहेंगे, अदालतें भी रहेंगी, मुकदमों पर फैसले भी होंगे, लेकिन दिल और आत्मा का लोप हो जाएगा।इ तमाम जजों को न्यायमूर्ति भूइयां की इन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि न्यायापालिका के पास ना तो धन होता है, ना तलवार। उसमें लोगों का भरोसा ही उसकी कुल जमा-पूंजी है। बड़े परिदृश्य में देखें, तो मुद्दा सिर्फ न्यायपालिका नहीं है। सबको इसका ख्याल रखना चाहिए कि इसकी साख चूकने का अर्थ पूरी शासन व्यवस्था के औचित्य को संदिग्ध कर देगा।

भारत के साथ व्यापार समझौता करने को व्याकुल सारे मुल्क

हरिशंकर व्यास

पूरी दुनिया की भू राजनीति में उथलपुथल है। पिछले आठ दशक से ज्यादा समय से अमेरिका के सबसे भरोसे के सहयोगी रहे यूरोपीय देशों का भरोसा टूटा है तो चीन और रूस जैसे अमेरिका के घोषित प्रतिद्वंद्वियों या दुश्मनों को भी नए सिरे से अपनी नीतियां बनाने की जरुरत महसूस हो रही है। ट्रंप भले दावा करें कि उन्होंने आठ युद्ध रुकवाए हैं, हकीकत यह है कि उन्होंने सात युद्ध शुरू किए हैं। सीरिया से लेकर लीबिया, नाइजीरिया, वेनेजुएला, ईरान तक अमेरिका ने बमबारी की है। उन्होंने कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका के नक्शे का हिस्सा बता दिया है। दुनिया में इस समय युद्ध का खतरा मंडरा रहा है तो साथ साथ आर्थिक अनिश्चितता भी गहरी होती जा रही है।

राष्ट्रपति ट्रंप ने दुनिया भर के देशों के खिलाफ टैरिफ वार छेड़ा है। भारत के ऊपर भी 25 फीसदी जैसे को तैसा टैक्स और रूस से तेल खरीदने के वजह से 25 फीसदी का जुर्माना टैक्स लगाया है। इसके बावजूद दुनिया की भू राजनीतिक और वैश्विक व्यापार की हालत ने भारत के लिए बड़ा मौका बनाया है। ट्रंप की नीतियों से परेशान दुनिया के ज्यादातर देश भारत की ओर से देख रहे हैं। इसलिए नहीं कि भारत उनको कोई राहत दिला देगा। सबको पता है कि भारत ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर में कहीं नहीं है। लेकिन 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का बाजार होने की वजह से भारत की स्थिति सबसे लिए महत्वपूर्ण हो गई है। दुनिया भर के देशों को भारत में अपना सामान बेचना है। इसलिए दुनिया के सारे मुल्क भारत के साथ व्यापार समझौता करने को व्याकुल हैं। ब्रिटेन के साथ भारत की व्यापार संधि हो गई है। पिछले दिनों संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति अल नाह्यान भारत के दौरे पर आए तो दोनों देशों ने साझा व्यापार 25 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने का समझौता है। वैसे अब भी यूएई के साथ भारत का कारोबार साढ़े 12 लाख करोड़ रुपए का है।

यूरोपीय संघ के साथ भारत की मुक्त व्यापार संधि की सारी शर्तें तय हो गई हैं। अब इस संधि पर दस्तखत होने हैं। इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियेन और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष भारत के मेहमान होंगे। 26 जनवरी की परेड के अगले दिन 27 जनवरी को यूरोपीय संघ के साथ अंतिम वार्ता होगी और व्यापार संधि हो जाएगी। इसे उर्सुला वॉन डेर ने मदर ऑफ ऑल डील्स कहा है। जाहिर है कि यह संधि बहुत बड़ी होगी और एक साथ यूरोप के 27 देशों के साथ भारत के आसान शर्तों पर व्यापार करने की स्थितियां बनेंगी। लेकिन सवाल है कि इतने देशों के साथ आसान शर्तों पर व्यापार की संधियों से भारत को क्या हासिल होगा?

दुनिया के देशों को तो भारत का बाजार मिलेगा लेकिन भारत भी क्या उन देशों के बाजार में अपना कुछ बेच पाएगा? भारत के पास बेचने के लिए क्या है और जो है उसका बाजार कितना बड़ा है? असल में भारत ने अपने को निर्यातक बनाने की ठीक ढंग से तैयारी ही नहीं ही। अगर आप बारीकी से देखेंगे तो भारत आज भी वही चीजें दुनिया को बेचता हुआ है, जो ढाई हजार साल पहले मौर्य काल में भी भारत बेचता था। जब सिल्क रूट से कारोबार होता था तब भी भारत वही सामान बेचता था, जो आज बेचता है। वही कपड़े, वही रत्न, वही मसाले भारत तब भी बेचता था और आज भी बेचता है। इसमें थोड़ी बहुत और चीजें जरूर जुड़ी हैं लेकिन ऐसी नहीं हैं, जिससे भारत एक बड़ा निर्यातक देश बन जाए। 180 साल पहले गिरमिटिया मजदूर बाहर गन्ने के खेतों में काम करने के लिए गए थे और आज आईटी के पेशेवर कुलीगिरी करने के लिए दुनिया भर के देशों मे जाते हैं। सो दुनिया के देशों के साथ हो रही व्यापार संधियों के बीच बड़ा सवाल यह है कि भारत में विनिर्माण क्रांति कैसे हो और भारत किन चीजों का उत्पादन बढ़ाए, जिसका वैश्विक बाजार बन सकता है और भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह तेज हो? यह सवाल इसलिए है क्योंकि भारत में निवेशक नहीं आ रहे हैं। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पिछले चार महीने का आंकड़ा शुक्रवार, 23 जनवरी को छपा है। इसके मुताबिक नेट एफडीआई शून्य रहा है, पिछले चार महीनों में। इसका मतलब है कि जितना प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भारत में आया उससे ज्यादा भारत का पैसा निवेश होने के लिए विदेश गया। सो, नेट एफडीआई जीरो है। भारत का निर्यात का बिल हमेशा आयात बिल के मुकाबले बहुत कम होता है।

भारत और ईयू में मुक्त व्यापार संधि, भारत-यूरोप के मध्य कारोबार को बूस्टर-डोज?

डॉ. सुधीर सक्सेना

लगभग दो दशक की कवायद के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के मध्य मुक्त व्यापार संधि (एफटीए) पर हस्ताक्षर हो गए। इस संधि के अमल में आने में यद्यपि थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अमेरिका के टैरिफ युद्ध के मटमैले साये में यूरोपीय देशों के लिए भारत के विशाल बाजार के दरवाजे खुल गए हैं और कुछ ही बरसों में भारतीय बाजार यूरोपीय साजो-सामान से पट जाएंगे। इसके फलस्वरूप भारतीय उपभोक्ताओं को फ्रेंच वाइन समेत तरह-तरह की शराब और कारों के विकल्प सस्ती कीमतों पर उपलब्ध होंगे। भारतीय महिलाएँ इस बात पर इतराएँगी कि अब उन्हें यूरोपीय सौंदर्य प्रसाधन और परिधान बेहतर गुणवत्ता के साथ कम कीमतों पर मिल सकेंगे।

गौरतलब है कि भारत और यूरोपीय यूनियन के मध्य एफटीए के लिए वार्ता की शुरुआत डॉ. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्रित्वकाल में वर्ष 2007 में हुई थी। वर्ष 1992 में मास्त्रिख्त संधि के बाद अगले ही वर्ष रोम में सात देशों की मौजूदगी में ईयू अस्तित्व में आया था। वर्ष 2009 में लिस्बन समझौते से इसे गति और विस्तार मिला। आज यूरोप-महाद्वीप के 27 देश इसके सदस्य हैं। बेल्जियम में इसका मुख्यालय है। इसका ध्येय-वाक्य है-'अनेकता में एकताइ। इसकी मुद्रा यूरो है, अपना राष्ट्रगान है और वैश्विक साख है। पाबंदियों और टैरिफ के अनिश्चित और नाजुक दौर में ईयू की महत्ता बढ़ गई है। इस बीच एक बड़ी घटना यह भी हुई कि यूके वर्ष 2020 में ईयू से बाहर हो गया, लिहाजा इस दूरगामी महत्व की संधि का लाभ उसे नहीं मिलेगा।

ईयू की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयेन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हस्ताक्षरित एफटीए को भारत और यूरोप के मध्य कारोबार के लिहाज से 'मील का पत्थरइ माना जा सकता है। डोनाल्ड ट्रंप के दंभ और धमकियों के दौर में इस संधि को यूरोपीय देशों की उद्योग-धंधों के लिए 'बूस्टर डोजइ कहा जा सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक का आभासी उद्घाटन करते हुए कहा कि यह संधि 'सभी सौदों की जननीइ है। उनका कहना था कि यह डील भारत में कपड़ा, रत्न, आभूषण, चमड़ा और जूट जैसे विभिन्न क्षेत्रों को फायदा पहुँचाएगी। उन्होंने कहा कि यह करार भारत की उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करेगा और सर्विस सेक्टर को नया संबल देगा।

इस महत्वपूर्ण संधि के तत्काल लागू न होने का कारण यह है कि पहले ईयू के सदस्य देशों की भाषाओं-जैसे फ्रेंच, जर्मन, इतालवी आदि-में इसका कानूनी दस्तावेज प्रकाशित होगा और फिर सभी धाराओं की सदस्य देशों में 'लीगल स्क्रबिंगइ होगी। तत्पश्चात यूरोपीय परिषद की औपचारिक मंजूरी और यूरोपीय संसद की सहमति आवश्यक है। इसके बाद भारतीय संसद की पुष्टि के उपरांत यह संधि लागू होगी। इन प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद इसके इस वर्ष के भीतर अमल में आने की उम्मीद की जा सकती है।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ पुष्परंजन मानते हैं कि इस बूस्टर डोज से ईयू के सदस्य देशों को बहुविध लाभ होगा। उनका मानना है कि भारत ने किसी भी व्यापारिक सहयोग को इतनी बड़ी ट्रेड ओपनिंग पहले कभी नहीं दी। उनकी बात की पुष्टि यूरोपीय कमीशन के आधिकारिक बयान से होती है। इससे यूरोपीय देशों के माल की भारतीय बाजारों में पहुँच और खपत आसान हो जाएगी। कमीशन ने एक चार्ट के जरिये वर्ष 2024 के आकलन के आधार पर बताया है कि मशीनरी और इलेक्ट्रिक उपकरणों पर उसे 16.3 बिलियन यूरो टैरिफ देने पड़े थे। अब इसके शून्य होने से बड़ा लाभ होगा। इसी तरह विमान और अंतरिक्ष यान निर्यात पर प्रदत्त 11 प्रतिशत के मान से 6.4 अरब यूरो की बचत होगी।

कल्पना कीजिए कि मशीनरी पर 44 प्रतिशत, रसायनों पर 22 प्रतिशत और फार्मास्यूटिकल्स पर 11 प्रतिशत टैरिफ यदि शून्य हो जाता है, तो यूरोपीय कंपनियों को कितना मुनाफा होगा। ऑप्टिकल, मेडिकल और सर्जिकल उपकरणों पर 27.5 प्रतिशत टैरिफ यदि हट जाए तो करीब तीन बिलियन यूरो बचेंगे। प्लास्टिक पर जीरो टैरिफ से दो बिलियन से अधिक की बचत होगी। यदि लोहे और इस्पात पर 22 प्रतिशत टैरिफ निरस्त होता है तो डेढ़ अरब यूरो से अधिक की बचत होगी। संधि से पहले पारस्परिक कारोबार से आठ लाख नौकरियों का समर्थन मिलता रहा है, अब इसमें भारी बढ़ोत्तरी होगी।

इस संधि से यूरोपीय किसानों की बाँछें खिलना स्वाभाविक है, क्योंकि एग्रो-फूड पर 36 प्रतिशत शुल्क में कमी से उन्हें बड़ा बाजार मिलेगा। संधि से मदिरा प्रेमी भी खुश होंगे, क्योंकि वाइन पर 150 प्रतिशत टैक्स घटकर 30 प्रतिशत पर आ जाएगा। बीयर पर टैक्स 110 प्रतिशत से 50 प्रतिशत होगा। लगभग 350 तरह के फलों, फलों के रस, चॉकलेट, ब्रेड, पेस्ट्री, सॉसेज और मांसाहारी व्यंजनों पर भी टैरिफ घटने से ये भारतीयों को सस्ते में मिलेंगे।

फिलहाल यूरोपीय संघ के देशों में इस संधि के नफे-नुकसान पर बहस जारी है। ईयू की अध्यक्ष उर्सुला का कहना है कि इस संधि से लाखों नौकरियाँ सृजित होंगी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा कहते हैं कि हम दो अरब लोगों के लिए बाजार बना रहे हैं।

अब यक्ष प्रश्न यह है कि क्या भारतीय कंपनियाँ और किसान आयातित चीजों की बाढ़ के बीच यूरोपीय मानकों और प्रतिस्पर्धा का सामना कर सकेंगे? देखना दिलचस्प होगा कि भारत के 140 करोड़ और यूरोप के 45 करोड़ लोगों के लिए एफटीए कितना बड़ा अवसर लेकर आता है? पुष्परंजन का यह सवाल वाजिब है कि यह भी देखना होगा कि इस संधि का भारत-अमेरिका और भारत-चीन संबंधों व व्यापार पर क्या असर पड़ता है?

फोकस

धान खरीदी और जप्ती मामले में प्रदेश में पहले पायदान पर रहा महासमुंद जिला

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के अंतर्गत जिला महासमुंद में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य कलेक्टर विनय लंगेह के मार्गदर्शन में सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। जिले में स्थापित 182 धान उपार्जन केंद्रों के माध्यम से कुल 10,00,187.16 मीट्रिक टन धान की खरीदी की गई, जो प्रदेश में सर्वाधिक रही। शासन द्वारा जिले के लिए 11,93,570.00 मीट्रिक टन धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य निर्धारित किया गया था। गत खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में जिले में 11,04,273.24 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई थी। इस प्रकार गत वर्ष की तुलना में इस वर्ष 9.43 प्रतिशत कम धान खरीदी दर्ज की गई।

इस वर्ष धान खरीदी हेतु जिले में 1,60,118 किसान पंजीकृत थे, जिनमें से 1,48,418 किसान (92.69 प्रतिशत) ने खरीदी अवधि के दौरान अपना धान विक्रय किया, जो राज्य के औसत 91.22 प्रतिशत से अधिक है। वहीं जिले में 1,09,676 पंजीकृत कृषकों द्वारा धान विक्रय के पश्चात 9,883.24 हेक्टेयर रकबा का समर्पण कराया गया। अवैध धान परिवहन एवं भंडारण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु कलेक्टर विनय लंगेह के निर्देशन में राजस्व, खाद्य, मंडी एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सतत निगरानी की गई। अंतर्राज्यीय सीमाओं पर 16 जांच चौकियां स्थापित की गईं तथा एसडीएम एवं तहसीलदार के नेतृत्व में संयुक्त दल गठित किए गए।

इस सतत निगरानी एवं सख्त कार्रवाई के परिणामस्वरूप अवैध धान परिवहन एवं स्टॉकिंग के 399 प्रकरण दर्ज किए गए, जिनमें 1,69,862 क्विंटल धान जब्त किया गया। जबकि गत वर्ष केवल 184 प्रकरणों में 12,828.15 क्विंटल धान की जब्ती की गई थी। अवैध धान परिवहन के मामलों में जिला महासमुंद प्रदेश में प्रथम स्थान पर रहा। शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का यह संपूर्ण कार्य जिले में पारदर्शिता, अनुशासन और सुगमता के साथ संपन्न हुआ।

सुरक्षित सड़कें, सशक्त समाज की नींव है-विधायक चैतराम अटामी

दंतेवाड़ा। जिले के सिटी कोतवाली परिसर में 36वें राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक चैतराम अटामी उपस्थित रहे। उनके साथ नगर पालिका उपाध्यक्ष कैलाश मिश्रा, जनपद पंचायत सदस्य रामूराम नेताम, पुलिस अधीक्षक गौरव राय, उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) नसर उल्लाह सिद्दीकी, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस राहुल उइके, गोविंद दीवान, कमलजीत पाटले सहित मीडिया प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

कार्यक्रम में विधायक चैतराम अटामी ने अपने उद्बोधन में कहा कि पुलिस विभाग द्वारा लगातार चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा एवं जागरूकता अभियानों का सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है, जिससे सड़क दुर्घटनाओं में कमी आई है। उन्होंने कहा कि अधिकांश सड़क दुर्घटनाएं वाहन चालकों की लापरवाही, तेज गति, शराब पीकर वाहन चलाने एवं यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं। उन्होंने आम नागरिकों से अपील की कि वे स्वयं भी जिम्मेदार नागरिक बनें और अपने परिवार व समाज की सुरक्षा के लिए यातायात नियमों का पालन करें। साथ ही युवाओं को विशेष रूप से सावधानी बरतने की सलाह दी।

इस मौके पर पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने कहा कि सड़क सुरक्षा केवल पुलिस की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर नागरिक की साझा जिम्मेदारी है। उन्होंने बताया कि हेलमेट, सीट बेल्ट, निर्धारित गति सीमा और यातायात संकेतों का पालन न करने से गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं, जिनमें कई बार जान तक चली जाती है। इस अवसर पर उप पुलिस अधीक्षक (यातायात) नसर उल्लाह सिद्दीकी ने 01 जनवरी 2026 से 31 जनवरी 2026 तक आयोजित राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत जिले में किए गए विभिन्न जागरूकता कार्यक्रमों, रैली, स्कूल-कॉलेजों में संवाद, पोस्टर प्रदर्शनी एवं यातायात नियमों के प्रचार-प्रसार की जानकारी दी। कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय बारसूर के छात्र-छात्राओं द्वारा सड़क सुरक्षा पर आधारित सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्हें उपस्थित जनों ने सराहा।

सतत विकास के लिए प्रकृति के साथ संतुलन आवश्यक - राज्यपाल डेका

संरक्षण क्षमता महोत्सव '2025-26' का राज्यपाल रमेन डेका ने किया उद्घाटन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

बिजली के दुरुपयोग रोकने और हर स्तर पर ऊर्जा संरक्षण पर दिया बल

श्री डेका ने कहा कि जागरूकता केवल बोलने से नहीं आती, बल्कि इसे हमारी दिनचर्या और आदतों का हिस्सा बनाना होगा। उन्होंने बिजली के दुरुपयोग को रोकने और हर स्तर पर ऊर्जा संरक्षण की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि भविष्य में पेट्रोल और डीजल के सीमित होने पर हमें ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसके लिए ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना होगा। अत्यधिक पेट्रोल ,डीजल उपयोग से पर्यावरण भी प्रदूषित होता है, इसलिए संतुलन बनाना जरूरी है।

पेट्रोलियम उत्पादों के विवेकपूर्ण उपयोग एवं ऊर्जा संरक्षण के उद्देश्य से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल एवं गैस कंपनियों के सहयोग से संरक्षण क्षमता महोत्सव 'सक्षम 2025-26' का आयोजन 1 से 14 फरवरी तक किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम का उद्घाटन आज स्थानीय सर्किट हाउस में राज्यपाल रमेन डेका ने किया।

राज्यपाल रमेन डेका ने कहा कि सक्षम एक अत्यंत महत्वपूर्ण जन-जागरूकता कार्यक्रम है, जो आने वाली पीढ़ियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने कहा कि सभ्यता के विकास के साथ मानव को ऊर्जा के अनेक साधन प्राप्त हुए हैं, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से प्रकृति और भावी पीढ़ियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि अतिरिक्त दोहन से नुकसान होता है, इसलिए सतत विकास के लिए प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। स्वच्छ हवा और स्वच्छ पानी हमारे मूलभूत अधिकार हैं। नदियों और पेड़ों को उनके प्राकृतिक स्वरूप में सुरक्षित रखना चाहिए।

राज्यपाल ने कीटनाशकों के अंधाधुंध प्रयोग और माइक्रो-प्लास्टिक से होने वाले दुष्प्रभावों की ओर भी ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने कहा कि माइक्रो-प्लास्टिक का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और यह अब गौ माता के दूध में भी पाया जा रहा है। प्रकृति को सबसे अधिक नुकसान मनुष्य स्वयं पहुंचा रहा है, इसलिए शिक्षा और जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।

राज्यपाल ने 'एक पेड़ मां के नाम' लगाने का आह्वान करते हुए जल संरक्षण पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जल का अत्यधिक दोहन हो रहा है। बड़े किसानों को अपने खेतों में डबरी निर्माण करना चाहिए, जिससे सामूहिक लाभ हो सके। साथ ही पुराने तालाबों और डबरियों के पुनर्जीवन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है और समाज के प्रति हमारा भी दायित्व बनता है।

कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन नितिन चव्हाण राज्य स्तरीय समन्वयक एवं मंडल प्रमुख इंडियन ऑयल द्वारा दिया गया। आभार प्रदर्शन हिंदुस्तान पैट्रोलियम के नितिन श्रीवास्तव ने किया। इस अवसर पर इंडियन ऑयल, भारत पैट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम तथा गेल के वरिष्ठ अधिकारी गण, कमर्चारी, विद्यार्थी तथा नागरिक गण उपस्थित थे।

ताला की विरासत से बिलासपुर और छग को मिली वैश्विक पहचान : मंत्री अरुण

दो वर्षों में 200 करोड़ से अधिक के सड़क कार्य स्वीकृत, शेष सड़कों को तीन साल में पूरा करने का दिया भरोसा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने ताला महोत्सव के दूसरे दिन सांस्कृतिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि मनियारी नदी के तट पर स्थित ताला गांव की देवरानीझजेठानी मंदिर तथा रुद्र शिव की अद्वितीय प्रतिमा ने न केवल बिलासपुर, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ को देश-दुनिया में विशेष पहचान दिलाई है। इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए राज्य सरकार पूरी तरह वचनबद्ध है।

उप मुख्यमंत्री श्री साव ने कहा कि बीते दो वर्षों में क्षेत्र में 200 करोड़ रुपये से अधिक की लागत के आठ महत्वपूर्ण सड़क निर्माण कार्यों को स्वीकृति मिली है। उन्होंने कहा कि वरिष्ठ विधायक धरमलाल कौशिक अपने क्षेत्र के विकास को लेकर सदैव चिंतित रहते हैं, इसी कारण यहां अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। जो भी सड़कें अभी शेष हैं, उन्हें भी स्वीकृत कर आगामी तीन वर्षों में पूर्ण किया जाएगा।

श्री साव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रत्येक गारंटी को मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व वाली सरकार धरातल पर उतार रही है। उन्होंने बताया कि कल ही महतारी वंदन योजना की 24वीं किस्त जारी की गई है, जिसके तहत सभी पात्र महिलाओं के खातों में एक-एक हजार रुपये जमा किए गए हैं। इससे मेला-मड़ई में महिलाओं की भागीदारी और रौनकता में वृद्धि हुई है।

विधायक धरमलाल कौशिक ने अपने संबोधन में कहा कि इस वर्ष से ताला महोत्सव में दिन के समय सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत एक सराहनीय पहल है, जिससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि ताला की रुद्र शिव प्रतिमा जैसी मूर्ति विश्व में कहीं और नहीं है, जिसके शरीर और चेहरे पर उकेरी गई विभिन्न जीव-जंतुओं की आकृतियां इसकी अद्वितीय विशेषता हैं।

उन्होंने बताया कि उप मुख्यमंत्री अरुण साव के प्रयासों से बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में दो वर्षों में लगभग 200 करोड़ रुपये के सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत हुए हैं। गांव-गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बन रहे हैं, पीने का पानी, चावल और इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड आम जनता को उपलब्ध हो रहा है। क्रेडा के अध्यक्ष भूपेंद्र सवन्नी ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि क्रेडा की ओर से मंदिर परिसर में 11 लाख रुपये की लागत से दो हाई मास्ट सोलर लाइट स्वीकृत की गई हैं।

जनपद पंचायत अध्यक्ष रामकुमार कौशिक और जिला पंचायत सदस्य गोविंद यादव सहित बड़ी संख्या में आसपास के गांवों के नागरिक कार्यक्रम में बड़ी संख्या में उपस्थित थे। लोक कलाकार सुनील सोनी के नेतृत्व में रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने दशर्कों को मंत्रमुग्ध कर महोत्सव का वातावरण उल्लासपूर्ण बना दिया।

पर्यटन व संस्कृति मंत्री अग्रवाल ने विजेताओं को किया पुरस्कृत

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री राजेश अग्रवाल ने विकासखंड लखनपुर के ग्राम बिनकरा, बगदर्री एवं जमगला में आयोजित खेल प्रतियोगिता में युवा खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया तथा खेलों के माध्यम से अनुशासन व टीम भावना की सीख पर जोर दिया।

लखनपुर विकासखंड के इन ग्रामीण क्षेत्रों में चले भव्य खेल आयोजन में श्री अग्रवाल ने खिलाड़ियों से भेंट की तथा उनकी प्रतिभा की सराहना की। स्थानीय युवाओं की उत्साहपूर्ण भागीदारी ने माहौल को रोमांचक बना दिया। मंत्री ने विजेताओं को सम्मानित किया तथा सभी को निरंतर प्रयास की प्रेरणा दी। श्री अग्रवाल ने कहा, कि खेल हमें अनुशासन, स्वस्थ जीवन शैली और टीम भावना के साथ कार्य करने की सीख देता है। उन्होंने ग्रामीण युवाओं को सक्रिय रहने तथा खेलों को जीवन का हिस्सा बनाने की सलाह दी। उन्होने कहा कि मेरी शुभकामनाएं हमारी असीम ऊर्जा से परिपूर्ण युवा शक्ति के साथ है। उन्होंने राज्य सरकार की खेल नीतियों का उल्लेख करते हुए बताया कि ग्रामीण स्तर पर ऐसे आयोजनों से प्रतिभाएं निखरेंगी। युवाओं से अपील की कि वे खेलों के माध्यम से स्वस्थ समाज के निर्माण में सहभागी बनें।

असम के अधिकारियों के प्रतिनिधि मंडल ने किया बस्तर का दौरा, विकास मॉडल का किया अध्ययन

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

बस्तर जिले में ग्रामीण विकास के कार्यों की सफलता अब पूर्वोत्तर भारत तक गूंज रही है। इसी क्रम में असम राज्य के उच्च अधिकारियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर का दौरा कर यहां के विकास मॉडल का गहन अध्ययन किया और इसे अपने राज्य में लागू करने की मंशा जाहिर की। संयुक्त आयुक्त श्री ध्रुव ज्योति नाथ और उपायुक्त राजेंद्र पांडे के नेतृत्व में पहुंचे इस दल ने लोहंडीगुड़ा विकासखंड के वनांचल क्षेत्रों का भ्रमण कर जमीनी हकीकत परखी।

लोहंडीगुड़ा के ग्राम पंचायत दाबपाल, एरंडवाल और छोटे परोदा में भ्रमण के दौरान असम के अधिकारियों ने प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के गृह प्रवेश कार्यक्रम में भाग लिया। सुदूर वन क्षेत्रों में बने पक्के मकानों को देखकर अधिकारी अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने फीता काटकर हितग्राहियों को चाबियां सौंपी और उनसे आत्मीय संवाद किया। हितग्राहियों के चेहरों की मुस्कान और उनके जीवन में आए बदलावों की कहानियों ने योजनाओं की सफलता को दर्शाया।

आवासों के निरीक्षण के बाद प्रतिनिधिमंडल ने मनरेगा के तहत निर्मित 'आजीविका डबरी' स्थलों का भी जायजा लिया। अधिकारियों ने ग्रामीणों को आर्थिक सशक्तिकरण का मंत्र देते हुए कहा कि डबरी का उद्देश्य केवल जल संचय नहीं, बल्कि आय का स्रोत बनना होना चाहिए। उन्होंने मछली पालन, बत्तख पालन और अन्य कृषि गतिविधियों को जोड़कर 'समन्वित खेती' का मॉडल अपनाने का सुझाव दिया, जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सहायक सिद्ध होगा।

बस्तर मॉडल को असम में अपनाने की पहल

दौरे के अंत में असम के अधिकारियों ने बस्तर में चल रहे कार्यों को एक 'सफल मॉडल' बताया। उन्होंने स्वीकार किया कि असम और बस्तर की भौगोलिक चुनौतियां काफी हद तक समान हैं और बस्तर द्वारा इन चुनौतियों के बीच विकास का रास्ता निकालना अनुकरणीय है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बस्तर के इस मॉडल को असम के ग्रामीण क्षेत्रों में भी अपनाया जाएगा।

बदलाव किसानों को पारंपरिक खेती के साथ नई तकनीक, फल, फूल, सब्जी एवं औषधीय फसलों को अपनाने दिया जोर

खेती-किसानी को बनाएंगे किसानों के लिए लाभदायक: केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

केन्द्रीय कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत के किसानों ने अपनी मेहनत और परिश्रम से देश की दिशा और दशा दोनों बदल दी है। वर्तमान में कृषि की विकास दर 4.45 प्रतिशत है, कृषि क्षेत्र में एक-दो प्रतिशत की वृद्धि भी बड़ी मानी जाती है। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना है तो परम्परागत खेती के अलावा फलों, सब्जियों मसाले एवं औषधि फसलों की खेती के साथ कृषि के उन्नत तकनीक को अपनाना होगा। केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान कुम्हारी में किसान मेला में शिरकत करते हुए यहां आयोजित कार्यक्रम को मुख्य अतिथि की आसंदी से सम्बोधित कर रहे थे।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि भारत आज चावल उत्पादन में दुनिया में नंबर वन बन चुका है और चीन को भी पीछे छोड़ दिया है। देश में 18 करोड़ टन चावल का उत्पादन हुआ है। छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहा जाता है। फल और सब्जी उत्पादन में भी भारत ने रिकॉर्ड तोड़ा है। सब्जियों की ग्रोथ रेट अद्भुत है और अब लोगों के दैनिक जीवन में फलों की खपत भी बढ़ी है।

उन्होंने कहा कि कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और किसान उसकी आत्मा। किसान केवल अन्नदाता नहीं बल्कि जीवनदाता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गौरवशाली, शक्तिशाली और आत्मनिर्भर विकसित भारत का निर्माण हो रहा है। खेती में प्रगति हुई है, लेकिन किसानों की आय बढ़ाने के लिए खेती को लाभ का व्यवसाय बनाना जरूरी है। इसके लिए परंपरागत खेती के साथ नई तकनीक, उन्नत बीज और फल, फूल, सब्जी एवं औषधीय फसलों की खेती को अपनाना होगा। आज छत्तीसगढ़ में उत्पादित सब्जियां अन्य देश के अन्य राज्यों में भेजी जा रही हैं।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने खेतों में नवाचार की सराहना करते हुए कहा कि यहां बैंगन की जड़ों पर टमाटर फल रहे हैं तो तीखी मिर्च में शिमला मिर्च उगाई जा रही है। यहां गन्ना, कपास, केला, ब्लूबेरी और ड्रैगन फ्रूट की खेती भी हो रही है। खेतों का दौरा करने के दौरान किसानों ने बताया गया कि धान की परंपरागत खेती में जहां 35 से 40 हजार रुपये की बचत होती है, वहीं सब्जी की खेती से दो लाख रुपये प्रति एकड़ तक शुद्ध लाभ संभव है।

किसान मेला में प्रगतिशील किसानों ने हाईटेक मंडी और प्रशिक्षण केंद्र के लिए भूमि की मांग रखी। इस पर मंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाएगा। उन्होंने नकली खाद और बीज की समस्या पर चिंता जताते हुए बताया कि संसद के आगामी सत्र में सीड एक्ट लाया जाएगा ताकि खराब बीज देने वालों पर कड़ी कार्यवाही हो सके। इसी तरह कीटनाशक (पेस्टिसाइड) कानून भी लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसंधान और रिसर्च को सरकार पूरा समर्थन देगी। इस दौरान उन्होंने फरवरी माह में दिल्ली में आयोजित होने वाले कृषि चिंतन शिविर की जानकारी देते हुए सभी प्रगतिशील किसानों को आमंत्रित किया।

केन्द्रीय कृषि मंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सर्वोच्च प्राथमिकता किसान हैं और सरकार किसानों का साथ कभी नहीं छोड़ेगी। उन्होंने कहा कि किसानों की खेती को फायदे की खेती बनाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर किसानों की खेती को अधिक लाभकारी बनाने के लिए हर संभव कदम उठाएगी। इस दौरान उन्होंने किसान मेला किसानों द्वारा संचालित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के कृषि उत्पाद एवं आधुनिक कृषि यंत्रों की प्रदर्शनी का अवलोकन किया।

प्रदेश के कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कृषि क्षेत्र में जो उल्लेखनीय प्रगति दिखाई दे रही है, उसके पीछे युवा और प्रगतिशील किसानों की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने कहा कि इन किसानों ने अपने नवाचार और मेहनत से प्रदेश को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई है। समारोह में कृषि के क्षेत्र में योगदान देने वाले युवा प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया गया।

इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेन्द्र यादव, सांसद विजय बघेल, अहिवारा विधायक डोमनलाल कोर्सेवाड़ा, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डे, पूर्व विधायक देवजीभाई पटेल एवं डॉ. दया राम साहू, जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती सरस्वती बंजारे सहित युवा प्रगतिशील किसान संघ के पदाधिकारी एवं किसान भाई बड़ी संख्या में उपस्थित थे।

शासन की संवेदनशीलता का है परिणाम कृत्रिम पैर पाकर फिर चला आत्मविश्वास

नई दृष्टिबिंदु / धमतरी

समाज कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ द्वारा दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु संचालित योजनाएँ आज जमीनी स्तर पर सकारात्मक बदलाव ला रही हैं। इसका सशक्त उदाहरण कुरुद तहसील के ग्राम बकली निवासी 60 प्रतिशत अस्थि बाधित अर्जुन लाल साहू की जीवन यात्रा है, जिन्हें राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र, माना कैंप रायपुर द्वारा निशुल्क आधुनिक कृत्रिम पैर प्रदान किया गया।

श्री साहू लंबे समय से शारीरिक अक्षमता के कारण चलने-फिरने में कठिनाई का सामना कर रहे थे। इससे न केवल उनका दैनिक जीवन प्रभावित हो रहा था, बल्कि आजीविका और सामाजिक सहभागिता में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी। समाज कल्याण विभाग के मार्गदर्शन में जब उनका पंजीयन राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र में कराया गया, तो विशेषज्ञ चिकित्सकों और तकनीशियनों द्वारा उनका समुचित परीक्षण किया गया। अत्याधुनिक तकनीक से उनके पैर का सटीक माप लेकर, उनकी आवश्यकता के अनुरूप कृत्रिम पैर का निर्माण किया गया।

कृत्रिम पैर प्राप्त करने के बाद श्री साहू के जीवन में नई उम्मीद की किरण जगी है। अब वे बिना सहारे चल पाने में सक्षम हो रहे हैं और आत्मनिर्भर जीवन की ओर अग्रसर हैं। उन्होंने शासन-प्रशासन एवं समाज कल्याण विभाग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कहा कि यह सहायक उपकरण उनके लिए केवल एक साधन नहीं, बल्कि सम्मान और स्वावलंबन की पुनर्प्राप्ति है।

माना कैंप रायपुर स्थित राज्य संसाधन एवं पुनर्वास केंद्र (Physical Referral Rehabilitation Center) राज्य के दिव्यांगजनों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। यहां कृत्रिम अंग निर्माण, फिजियोथेरेपी, परामर्श एवं पुनर्वास जैसी सुविधाएँ निरंतर उपलब्ध कराई जा रही हैं। केंद्र का उद्देश्य दिव्यांगजनों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ते हुए उन्हें आत्मनिर्भर बनाना है।

मनोरंजन जगत में श्रिया सरन के 25 साल पूरे, साझा किए अनुभव

मनोरंजन जगत में जानी-मानी अभिनेत्री श्रिया सरन ने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। अभिनेत्री ने इतने लंबे करियर में इंडस्ट्री में आए कई बड़े बदलावों को महसूस किया है। श्रिया सरन ने इस मौके पर अपने सफर, तकनीकी बदलावों और आज के दौर की चुनौतियों पर खुलकर बात की। श्रिया ने बताया कि जब उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की थी, तब फिल्म सेट्स का माहौल आज से बिल्कुल अलग था। उस समय इस्तेमाल होने वाली लाइट्स बेहद तेज होती थीं, जो आंखों को चुभती थी और कई बार कलाकारों के लिए असहज स्थिति पैदा कर देती थी। कैमरे भारी हुआ करते थे और तकनीक भी सीमित थी। शूटिंग के दौरान कलाकारों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था और कैमरे की आवाज सुनकर ही यह अंदाजा लगता था कि सीन शुरू हो चुका है। उस दौर में काम करना ज्यादा मेहनत और धैर्य की मांग करता था। उन्होंने कहा कि आज तकनीक ने फिल्म इंडस्ट्री को पूरी तरह बदल दिया है। अब सॉफ्ट लाइट्स का इस्तेमाल होता है, जिससे आंखों पर दबाव नहीं पड़ता। कैमरे पहले से कहीं ज्यादा हल्के और एडवांस हो गए हैं, जिससे शूटिंग न सिर्फ आसान बल्कि तेज भी हो गई है। इन बदलावों का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ है कि कलाकार अब तकनीकी परेशानियों से हटकर अपने अभिनय पर ज्यादा ध्यान दे पाते हैं और काम का माहौल भी पहले से ज्यादा आरामदायक हो गया है। श्रिया सरन ने इंडस्ट्री के वर्किंग सिस्टम में आए बदलावों पर भी बात की। उन्होंने कहा कि पहले कलाकारों को केवल एक मैनेजर के जरिए काम संभालना पड़ता था, लेकिन अब एजेंसियों का दौर है। आज कलाकारों को कई लोगों से तालमेल बैठाना पड़ता है। नई पीढ़ी के लोग नई सोच और नई जानकारी के साथ आते हैं, जो पुरानी पीढ़ी के लिए भी सीखने का मौका होती है। ऐसे में समय के साथ खुद को बदलना और नई चीजों को अपनाना बेहद जरूरी हो गया है। अपने 25 साल के करियर के उतार-चढ़ाव को याद करते हुए श्रिया ने कहा कि इतने लंबे सफर में भावनात्मक रूप से कई तरह के दौर आते हैं। कभी सब कुछ अच्छा लगता है, तो कभी इंसान खुद को अकेला और कमजोर महसूस करता है। ऐसे समय में अपने आसपास सही और सकारात्मक लोगों का होना बहुत जरूरी होता है, जो आपको संभालें और आगे बढ़ने की ताकत दें।

रानी ने कहा था, मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे: रणबीर कपूर

भूले हैं। रणबीर कपूर ने रानी मुखर्जी को याद करते हुए कहा कि 'सांवरिया' के दौरान रानी पहली शख्स थीं जिन्होंने उनसे कहा था कि अगर वह मेहनत करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे।

रणबीर के मुताबिक, उस समय जब उन्हें सबसे ज्यादा सहारे और भरोसे की जरूरत थी, रानी के शब्दों ने उन्हें भीतर से मजबूत बनाया। उन्होंने कहा कि वह रानी को सिर्फ एक बेहतरीन अभिनेत्री के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक इंसान के रूप में भी बहुत करीब से जानते हैं। उनकी गरिमा, आकर्षण और अभिनय प्रतिभा ने उन्हें हमेशा प्रभावित किया है। रणबीर का मानना है कि रानी मुखर्जी भारतीय सिनेमा की उन चुनिंदा अभिनेत्रियों में से हैं, जिन्हें पीढ़ियां याद रखेंगी।

उन्होंने कहा कि रानी की 30 साल की आइकॉनिक विरासत का जश्न मनाने के लिए पूरे इंडस्ट्री का एक साथ आना वाकई खास है। रानी ने अपने किरदारों और फिल्मों के चयन से न सिर्फ खुद को अलग पहचान दी, बल्कि स्क्रीन पर महिलाओं को दिखाने का नजरिया भी बदला है। रणबीर ने यह भी कहा कि रानी का सिनेमा हमेशा लोगों को खुशी देने और समाज को कुछ सोचने पर मजबूर करने वाला रहा है। इस बीच, रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' ने इंटरनेट पर तहलका मचा रखा है। यह फिल्म महिलाओं के खिलाफ अपराध जैसे गंभीर सामाजिक मुद्दे को फिर से मजबूती से उठाती है। इस बार कहानी देशभर में कम आय वर्ग से आने वाली 8-9 साल की मासूम बच्चियों के अपहरण के भयावह सच को सामने लाएगी।

पूरा भारतीय फिल्म उद्योग एकजुटता के साथ अभिनेत्री रानी मुखर्जी के सिनेमा में 30 साल पूरे होने का जश्न मना रहा है। यह जश्न रानी की चर्चित और दमदार फ्रेंचाइजी 'मर्दानी' की तीसरी फिल्म 'मर्दानी 3' के साथ मनाया जा रहा है, जो इन दिनों जबरदस्त चर्चा में है। इस जश्न में शामिल होकर रणबीर कपूर को भी बेहद खुशी और गर्व महसूस हो रहा है। रणबीर और रानी का रिश्ता सिर्फ सह-कलाकारों का नहीं, बल्कि सम्मान, प्रेरणा और भरोसे से भरा रहा है। रानी, रणबीर कपूर की डेब्यू फिल्म 'सांवरिया' में उनकी को-स्टार थीं और करियर की शुरुआत में उन्होंने रणबीर को जो आत्मविश्वास दिया, उसे वह आज भी नहीं

'बॉर्डर 2' देखने का अमीषा पटेल को बेसब्री है इंतजार

हाल ही में अभिनेत्री अमीषा पटेल ने 'बॉर्डर 2' को लेकर अपनी खुशी और उत्साह जाहिर किया। उन्होंने कहा कि फिल्म को लेकर वह बेहद उत्साहित हैं और खास तौर पर तारा सिंह जैसे आइकॉनिक किरदार की झलक देखकर उन्हें काफी रोमांच महसूस हो रहा है। अमीषा ने कहा कि उन्हें पूरा भरोसा है कि फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी समेत सभी कलाकारों ने शानदार काम किया होगा। उन्होंने यह भी कहा कि वह फिल्म और उसके गानों को बड़े पर्दे पर महसूस करने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रही हैं। फिल्म की तुलना को लेकर अमीषा पटेल ने साफ राय रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने अभी तक 'बॉर्डर 2' नहीं देखी है, लेकिन 1997 की 'बॉर्डर' जरूर देखी है। इसके बावजूद जिस तरह से दर्शक इस नई फिल्म को पसंद कर रहे हैं, उससे साफ है कि पूरी टीम ने बेहतरीन काम किया है। उन्होंने 'गदर' और 'गदर 2' का उदाहरण देते हुए कहा कि शुरुआत में दोनों फिल्मों की तुलना हुई थी, लेकिन 'गदर 2' की सफलता के बाद सभी ने माना कि वह अपने आप में एक अलग और शानदार फिल्म है।

अमीषा के मुताबिक फिल्मों की तुलना करना सही नहीं होता, क्योंकि इससे गलत धारणाएं बनती हैं और हर फिल्म को अपनी पहचान के साथ देखा जाना चाहिए। अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी 'बॉर्डर 2' में नई कहानियों और नए चेहरों को शामिल किया गया है। फिल्म में वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी भारतीय सेना के जवानों के किरदार में नजर आ रहे हैं, जबकि मोना सिंह, सोनम बाजवा, मेधा राणा और अन्या सिंह अहम भूमिकाओं में दिखाई दे रही हैं। 23 जनवरी को रिलीज हुई इस फिल्म के गाने भी दर्शकों के बीच खासे लोकप्रिय हो रहे हैं और उन्हें नॉस्टेल्जिया का एहसास दिला रहे हैं। 'बॉर्डर 2' को गुलशन कुमार और टी-सीरीज के बैनर तले बनाया गया है।

फिल्म के निर्माता भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता हैं। बता दें कि सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छी कमाई कर रही है और दर्शकों का दिल जीतने में भी सफल साबित हो रही है। 1997 में आई सुपरहिट और यादगार फिल्म 'बॉर्डर' की इस सीक्वल ने न सिर्फ पुरानी यादों को ताजा किया है, बल्कि नई पीढ़ी के दर्शकों को भी देशभक्ति के जज्बे से जोड़ दिया है। आम दर्शकों से लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग तक, हर तरफ फिल्म की चर्चा और तारीफ हो रही है।

अपनी सेहत को लेकर मजेदार किस्सा सुनाया ऋतिक रोशन ने

हाल ही में बॉलीवुड फिल्म निर्माता गोल्डी बहल की बर्थडे पार्टी में बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन को बैसाखी के सहारे चलते देखा गया था, जिसके बाद फैंस उनकी सेहत को लेकर चिंतित हो गए थे। अब अभिनेता ने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए इसकी वजह साफ कर दी है। ऋतिक ने बताया कि उनके बाएं घुटने में अचानक दर्द उभर आया, जिससे चलने-फिरने में दिक्कत होने लगी। उन्होंने लिखा कि उनके शरीर के हर हिस्से में जैसे कोई 'ऑन/ऑफ' बटन लगा हो। कभी बायां पैर जवाब दे देता है, तो कभी कंधा या दायां टखना अचानक काम करने से मना कर देता है। ऋतिक ने इसे सिर्फ शारीरिक नहीं, बल्कि एक तरह की मनोदशा भी बताया। अपने खास अंदाज में उन्होंने लिखा, 'कभी मेरे बाएं पैर को बैसाखी की जरूरत पड़ती है, तो कभी बायां कंधा और दायां टखना एक्टिव हो जाते हैं या अचानक बंद हो जाते हैं। लगता है मेरे शरीर के हर हिस्से की अपनी अलग ही मर्जी है।'

ऋतिक ने अपनी हालिया शूटिंग से जुड़ा एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया। उन्होंने बताया कि एक गंभीर सीन के दौरान उनका डायलॉग था 'क्या आप डिनर के लिए घर आना चाहेंगे?' लेकिन उनकी जुबान 'डिनर' शब्द बोलने से मना कर रही थी। ऐसे में उन्होंने हर टेक में चतुराई से 'डिनर' की जगह 'लंच' कहना शुरू कर दिया, क्योंकि शुरू था कि 'लंच' शब्द अभी भी बोला जा सकता था।

उन्होंने आगे लिखा कि पहली बार गलत शब्द निकलने पर हैरानी हुई, लेकिन जब वही गलती दोबारा हो गई तो उन्होंने सलमान खान स्टाइल में हाथ उठाकर रीटेक का इशारा किया, ताकि इसे मजेदार एक छोटी सी चूक साबित किया जा सके। ऋतिक ने अपनी इन शारीरिक परेशानियों को हल्के-फुल्के और आत्मस्वीकृति वाले अंदाज में पेश किया, जिससे फैंस भी राहत महसूस कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते शनिवार को बैसाखी के सहारे चलते हुए उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद से ही उनके चाहने वाले परेशान थे। बता दें कि ऋतिक रोशन अक्सर सोशल मीडिया पर फैंस से खुलकर जुड़ते हैं। इस बार उन्होंने अपनी सेहत से जुड़ी परेशानियों को ईमानदारी और मजाकिया अंदाज में साझा किया है।

माही विज फिर चर्चा में

टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस माही विज एक बार फिर चर्चा में हैं, लेकिन इस बार वजह उनकी कोई नई सीरीज या शो नहीं, बल्कि अपनी बेटी तारा के लिए किया गया खास तोहफा है। पति और अभिनेता जय भानुशाली से तलाक के बाद माही ने जिस मजबूती और आत्मनिर्भरता के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है, वह कई महिलाओं के लिए मिसाल बन चुकी है। तलाक के बाद माही को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हर आलोचना का जवाब अपनी उपलब्धियों से दिया। पहले खुद के लिए नई कार खरीदी, फिर अपने नए घर की झलक फैंस के साथ साझा की और अब उन्होंने अपनी नन्ही बेटी तारा को करीब 50 लाख रुपये की लग्जरी मिनी कूपर कार गिफ्ट कर सबका ध्यान खींच लिया है। बताया जा रहा है कि यह कार तारा का सपना थी, जिसे माही ने पूरा किया। सोशल मीडिया पर कार के साथ तस्वीरें वायरल होते ही फैंस माही की जमकर तारीफ कर रहे हैं। कई यूजर्स ने उन्हें 'स्ट्रॉन्ग सिंगल मदर' और 'इंस्पिरेशन' बताया।

फिटनेस का शानदार नमूना पेश किया अक्षरा सिंह ने

अपनी फिटनेस और मेहनत का भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने फिर शानदार नमूना पेश किया है। अभिनेत्री अपनी फिटनेस को लेकर बेहद गंभीर हैं और नियमित रूप से जिम में एक्सरसाइज करती हैं। उन्होंने अपनी कुछ नई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिनमें वे अपनी टोंड और फिट बॉडी फ्लॉन्ट करती नजर आईं। उनकी यह फिटनेस जर्नी फैंस के लिए मोटिवेशन का स्रोत बनी हुई है। इस बार भी उन्होंने अपने आधिकारिक इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें पोस्ट कीं, जिसमें वे लटकते हुए पुल-अप्स और हैंगिंग लेग रेज करती दिख रही हैं। कुछ तस्वीरों में वे ओपन जिम में एक्सरसाइज करती दिख रही हैं, तो कुछ में उनके मजबूत आर्म्स, टाइट एब्स और संपूर्ण फिट बॉडी साफ नजर आ रही है। स्पोर्ट्सवियर में उनका लुक एनर्जेटिक और आकर्षक लग रहा है। तस्वीरों को देखकर फैंस अंदाजा लगा सकते हैं कि अक्षरा फिटनेस को कितनी गंभीरता से लेती हैं। पोस्ट में उन्होंने सिर्फ एक इमोजी का इस्तेमाल किया है, लेकिन फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। अक्षरा सिंह ने सत्यमेव जयते से डेब्यू किया था और इसके बाद उन्होंने भोजपुरी सिनेमा में कई हिट फिल्में दी हैं, जिनमें सत्या, सरकार राज, मां तुझे सलाम, धड़कन, तबादला, सत्य, प्रेम विवाह, साथिया, दिलेर, सौगंध गंगा मैया के शामिल हैं। इसके अलावा वे टीवी शो बिग बॉस ओटीटी, सर्विस वाली बहू, पोरस और काला टीका में भी नजर आ चुकी हैं। अभिनेत्री जल्द ही निरहुआ के साथ फिल्म सात फेरे चार वचन और अम्बे है मेरी मां में दिखाई देंगी। दोनों फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी है और अब ट्रेलर रिलीज का इंतजार है।

सोहा अली ने जताया पति पर प्यार

बॉलीवुड के सबसे सादगी भरे और पसंदीदा कपल्स में शुमार सोहा अली खान और कुणाल खेमू आज अपनी शादी की 11वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस खास मौके पर सोहा अली खान ने अपने पति कुणाल खेमू के लिए एक भावुक और प्यार से भरा पोस्ट सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसने फैंस का दिल जीत लिया है। सोहा ने अपनी शादी के सफर को याद करते हुए लिखा कि कुणाल से शादी करना उनके जीवन का सबसे अच्छा फैसला रहा है। उन्होंने पति के साथ बिताए पलों, दोस्ती, समझ और सपोर्ट को अपने रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत बताया। पोस्ट के साथ शेयर की गई तस्वीरों में कपल की शानदार केमिस्ट्री साफ झलक रही है। सोहा और कुणाल ने 25 जनवरी 2015 को शादी की थी। शादी के बाद दोनों ने न सिर्फ अपने प्रोफेशनल करियर में संतुलन बनाए रखा, बल्कि अपनी पर्सनल लाइफ को भी हमेशा लाइमलाइट से दूर और सादगी से जिया। दोनों एक बेटी इनाया के माता-पिता हैं और अक्सर फैमिली मोमेंट्स सोशल मीडिया पर शेयर करते रहते हैं। सोहा के इस पोस्ट पर फैंस और सेलेब्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं। कई लोगों ने कपल को 'रियल रिलेशनशिप गोल्स' बताया है।

हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से हो गया है दूर: प्रकाश राज

नेशनल अवॉर्ड विनर प्रकाश राज एक बार फिर से अपने बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उनका मानना है कि मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से दूर हो गया है, और ज्यादा से ज्यादा नकली और पैसे पर फोकस हो गया है। प्रकाश ने हिंदी सिनेमा की खुलकर आलोचना की। रिपोर्ट के अनुसार, प्रकाश ने कहा, अभी के समय में, मुझे लगता है कि मलयालम और तमिल सिनेमा बहुत अच्छी फिल्में बना रहे हैं... दूसरी ओर, हिंदी सिनेमा अपनी जड़ों से भटक गया है। सब कुछ सुंदर, शानदार, प्लास्टिक जैसा दिखता है, जैसा कि आप मैडम तुसाद म्यूजियम में देखते हैं। हमारे (साउथ सिनेमा) पास अभी भी दिखाने के लिए कहानियां हैं; तमिल के नए युवा डायरेक्टर दलित मुद्दों पर बात कर रहे हैं और इससे बहुत उम्मीद मिलती है। इंडस्ट्री ने दर्शकों के साथ अपना कनेक्शन खो दिया है।

प्रकाश राज ने आगे कहा, मल्टीप्लेक्स आने के बाद, बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री सिर्फ मल्टीप्लेक्स के लिए फिल्में बनाने लगी, क्योंकि वे अच्छा चल रही थीं। वे उस पेज 3 कल्चर में चले गए, और इसके साथ ही ग्रामीण राजस्थान और बिहार से उनका कनेक्शन खत्म हो गया... आज, सब कुछ पैसे और दिखावे के बारे में है -- रील्स, पेज 3 कवरेज, और जोरदार सेल्फ-प्रमोशन। मुझे लगता है कि इस चक्कर में इंडस्ट्री ने दर्शकों के साथ अपना कनेक्शन खो दिया है। बता दें कि प्रकाश राज आखिरी बार हिंदी फिल्म तेरे इश्क में में दिखे थे। इस मूवी में उनके साथ धनुष और कृति सेनन लीड रोल में थे। इस मूवी में उन्होंने धनुष के पिता का किरदार निभाया था।

प्रकाश राज अब जल्द ही पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा जना नायकन में नजर आएंगे। यह एक्टर के तौर पर विजय की आखिरी फिल्म होगी। प्रकाश राज हिंदी के अलावा कन्नड़, तमिल, मलयालम, इंग्लिश और मराठी फिल्मों के लिए काम करते हैं। वो 5 बार नेशनल अवॉर्ड जीत चुके हैं। उन्होंने अपने करियर में 400 से ज्यादा फिल्में की हैं। एक्टर प्रकाश राज ने साउथ से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक्टिंग का दम दिखाया। प्रकाश अपनी शानदार फिल्मों जैसे सिंघम, दबंग 2 और वांटेड के लिए जाने जाते हैं। प्रकाश अपने बेबाक बयानों के लिए भी जाने जाते हैं।

ब्रह्माकुमारी संस्था के 90वें वर्ष में प्रवेश पर महाशिवरात्रि परिवर्तन मास का शुभारंभ

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

अंतर्राष्ट्रीय संस्था प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय विश्व विद्यालय के 90वें वर्ष में प्रवेश होने के उपलक्ष में सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में वसंत ऋतु के आगमन पर महाशिवरात्रि पर्व (शिव जयंती उत्सव) का शुभारंभ किया गया। भिलाई सेवा केंद्रों की निदेशिका ब्रह्माकुमारी आशा दीदी ने कहा कि यह समय विश्व परिवर्तन, स्वयं के परिवर्तन और संस्कारों के परिवर्तन का समय है। पुरानी दुनियां बदल कर नई दुनियां का आगमन इस सृष्टि पर होगा यह परिवर्तन का समय है, हमारी जिम्मेवारी है कि हमें नई दैवीय दुनियां के लिए हमारे संस्कारों को भी सतोंप्रधान दैवीय बनाना है नई दुनियां अर्थात संपूर्ण पावन जहां एक राज्य एक धर्म एक भाषा थी।

उन्होंने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व तक सभी अपने कमी कमजोरी को आत्म चिंतन द्वारा भोलेनाथ शिव पर अर्पित करेंगे। महत्व समय पर परिवर्तन का है। आपने बताया कि दूसरों को

बदलने की अवगुण देखने की वृति को चेंज करो, देखना है तो विशेषताएं देखो। सोचा और किया करेंगे देखेंगे नहीं। तीन श्रेष्ठ आसन (तख्त) के बारे में बताया कि पहला भृकुटी के मध्य आत्मा मालिक का तख्त ,दूसरा शिव परमात्मा(भोलेनाथ)का दिल तख्त,तीसरा नई सृष्टि के राज्य अधिकारी का तख्त अर्थात मैं आत्मा भृकुटी के मध्य में निवास सर्व शक्तिवान परमात्मा की संतान इन शरीर रूपी कर्मेंद्रियों द्वारा कार्य कराकर परमात्मा के दिल तख्त पर विराजमान भविष्य नई दैवीय दुनियां की सर्व गुण संपन्न राज्य अधिकारी आत्मा हूं। हमें हमारे श्रेष्ठ दैवीय संस्कारों से नई दुनियां की स्थापना करनी है, धर्म अर्थात धारणा।

ब्रह्माकुमारी दीदीयों ने 90 वर्ष के उपलक्ष्य में दीपक जलाकर शिव ध्वज फहराकर महाशिवरात्रि परिवर्तन मास की शुरुआत की। सभी ब्रह्मा वत्स मेरा उपहार शिव परमात्मा को अपने परिवर्तन का स्व उन्नति का चार्ट भरकर अपनी कमी कमजोरियों को महाशिवरात्रि के दिन परमात्मा शिव भोलेनाथ को अर्पण करेंगे।

इस अवसर पर फूलों से विशाल ज्योतिर्लिंग की रंगोली बनाई गई। पीस ऑडिटोरियम और परिसर को शिव ध्वजों से सुंदर सजाया गया।

खास खबर

शासकीय कार्यालयों में अमर शहीदों को दी गई श्रद्धांजलि

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों की आहुति देने वाले अमर शहीदों की स्मृति में आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रशासनिक अधिकारियों ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। कलेक्टर अभिजीत सिंह सहित प्रशासन के समस्त अधिकारी एवं कमर्चारियों ने दो मिनट का मौन धारण कर अमर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इसी क्रम में जिला पंचायत के सभाकक्ष में भी श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य कायर्पालन अधिकारी बजरंग दुबे सहित जिला पंचायत के सभी अधिकारी-कमर्चारियों ने दो मिनट का मौन रखकर अमर शहीदों को नमन किया। इसी क्रम में जिले की सभी शासकीय कार्यालयों में अधिकारी-कमर्चारियों ने अमर शहीदों को मौन श्रद्धांजलि दी।

कल सुबह से शुरू होगा खास इबादत का सिलसिला

भिलाई। शबे बराअत के मौके पर 3 फरवरी को शहर का मुस्लिम समुदाय मस्जिदों, घरों और कब्रिस्तान में खास इबादत करेगा। दुआओं का यह सिलसिला मंगलवार 3 फरवरी को सुबह से शुरू होगा जो देर रात तक जारी रहेगा। कब्रिस्तान हैदरगंज इंतेजामिया कमेटी कैम्प-1 की ओर से इस मौके पर कई आयोजन रखे गए हैं। वहीं तमाम जरूरी तैयारियां कर ली गई हैं। शहर की तमाम मस्जिदों में शानदार रोशनी की गई है।

कब्रिस्तान हैदरगंज के हॉल में रविवार सुबह 7:30 बजे से कुरआन ख्वानी व दुरूद ख्वानी का सिलसिला शुरू होगा। इसके बाद सुबह 10 बजे फातिहाख्वानी और इज्तेमाई दुआएं होगी। शाम को जलसे की शुरूआत तकरीर व नात से होगी। यहां कब्रिस्तान हैदरगंज में रात तकरीबन 09:30 बजे इमाम ए आजम अबू हनीफा कॉन्फ्रेंस व महफिल ए शबे बराअत होगी, जिसमें मेहमान ए खुसूसी सैयद मुहम्मद महमूद अशरफ अशरफी अल जीलानी किछौछा शरीफ उत्तर प्रदेश होंगे।

शहर की तमाम मस्जिदों में शबे बराअत पर शाम की नमाज (मगरिब) के बाद तीन मरतबा सूरए यासीन शरीफ सुनाया जाएगा और लोग 2-2 रकअत के साथ नफिल नमाज पढ़ेंगे। इसके बाद दुआएं की जाएगी। जामा मस्जिद सेक्टर-6 में शाम को मगरिब की नमाज के ठीक बाद सूरए यासीन सुना जाएगा और लोग नफिल नमाज पढ़ेंगे। शहर की दूसरी मस्जिदों में भी यह आयोजन होगा। भिलाई नगर मस्जिद ट्रस्ट के मातहत हैदरगंज कब्रिस्तान इंतजामिया कमेटी ने शबे बराअत को देखते हुए तैयारी पूरी कर ली गई है।

खुशखबरी राजिम कुंभ मेले में जाने वालों के लिए रायपुर-राजिम के बीच चलेगी मेमू स्पेशल

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

छत्तीसगढ़ के धार्मिक नगर राजिम में 1 फरवरी से 15 फरवरी तक आयोजित होने वाले राजिम कुंभ कल्प मेले को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यात्रियों की सुविधा के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। मेले में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को ध्यान में रखते हुए रायपुर और राजिम के बीच मेमू स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आवागमन में आसानी मिल सके।

रेलवे द्वारा जारी जानकारी के अनुसार रायपुर से राजिम के लिए ट्रेन संख्या 08755 दोपहर 11.55 बजे रवाना होगी और मंदिर हसौद, सीबीडी (पीएच), केंद्री, अभनपुर और मानिक चौरी स्टेशनों पर ठहराव के बाद 1.20 बजे राजिम पहुंचेगी। इसी तरह वापसी में ट्रेन संख्या 08756 दोपहर 2.00 बजे राजिम स्टेशन से चलकर विभिन्न स्टेशनों पर रुकते हुए 3.30 बजे रायपुर स्टेशन पहुंचेगी।

इसके अलावा एक और जोड़ी मेमू स्पेशल ट्रेन श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए चलाई जा रही है। ट्रेन संख्या 08757 रायपुर स्टेशन से दोपहर 2.30 बजे रवाना होकर शाम 4.00 बजे राजिम पहुंचेगी। वहीं राजिम से रायपुर के लिए ट्रेन संख्या 08758 सुबह 8.30 बजे प्रस्थान करेगी और सुबह 10.00 बजे रायपुर स्टेशन पहुंचेगी।

रेलवे अधिकारियों का कहना है कि इन विशेष ट्रेनों के संचालन से कुंभ कल्प मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को सुरक्षित, सुगम और किफायती यात्रा का विकल्प मिलेगा। साथ ही भीड़ प्रबंधन को बेहतर बनाने में भी मदद मिलेगी। यात्रियों से अपील की गई है कि वे यात्रा से पहले समय-सारिणी की जानकारी लेकर ही स्टेशन पहुंचें और रेलवे के दिशा-निर्देशों का पालन करें।

जिला शिक्षा अधिकारी ने ली प्रधान पाठकों की ली बैठक, स्कूलों का किया औचक निरीक्षण

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

कक्षा पांचवीं/आठवीं केन्द्रीकृत वार्षिक परीक्षा सत्र 2026 के आयोजन के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी दुर्ग द्वारा विकासखंड दुर्ग एवं पाटन के समस्त प्राथमिक-माध्यमिक शासकीय/अनुदान प्राप्त छग माध्यमिक शिक्षा मण्डल से सबद्ध अशासकीय गैर अनुदान प्राप्त विद्यालय के प्रधान पाठकों की बैठक ली गई।

बैठक में परीक्षा आयोजन के संबंध में राज्य से प्राप्त समस्त निर्देशों से अवगत कराया गया तथा समय सीमा में समस्त कार्यों के संपादन हेतु निर्देश दिये गये। विद्यालय स्तर पर ब्लूप्रिंट के आधार पर सेंपल प्रश्न पत्रों का निर्माण कर विद्यार्थियों को परीक्षा तिथि के पूर्व तक नियमित अभ्यास कराने के निर्देश दिये गये। प्रायोजन कार्य कक्षा पांचवी में 5-5 अंक कुल 10 अंक के दो प्रायोजना कार्य एवं कक्षा आठवीं में 10-10 अंक के कुल 20 अंक के दो प्रायोजना कार्य 28 फरवरी तक अनिवार्य रूप से पूर्ण कर प्रत्येक विद्याथिर्यों के अंकों की सूची तैयार कर 3 मार्च तक विकासखंड शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।

25 फरवरी तक कक्षा पांचवी एवं आठवीं के विद्याथिर्यों को ब्लूप्रिंट अनिवार्यतः लिखवाया जाये ताकि उस आधार पर वे परीक्षा की तैयारी कर सके। किसी भी बच्चे को वार्षिक परीक्षा से वंचित नहीं करने के निर्देश दिये गये। 30 जनवरी को जिले के शासकीय प्राथमिक शाला सिकोला, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला तुलसी, खुड़मुड़ी, शा.स.उ.मा.वि. खुड़मुड़ी का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण दौरान शालाएं संचालित पाया गया।

निरीक्षण के दौरान सभी प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक/हायर सेकेण्डरी के संस्था प्रमुखों को मध्यान्ह भोजन निर्धारित मीनू अनुसार प्रदाय करने, बारहखड़ी, पहाड़ा पुस्तक वाचन के नियमित अभ्यास कराने, विद्याथिर्यों की शत-प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चित किये जाने तथा नियत समय पर अनिवार्य उपस्थिति के निर्देश दिये। इसी प्रकार हाई/ हायर सेकेण्डरी विद्यालयों के प्राचार्यो को नियमित प्रायोगिक कार्य करने, ब्लू प्रिंट के अनुरूप 05 वर्षो के प्रश्न पत्रों को हल कराने, तिमाही, छमाही परीक्षा के आधार पर चिन्हांकित विद्यार्थीयों को सिमित पाठ्यक्रम में बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कराने एवं प्रायोगिक परीक्षा के बाद भी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व तक विद्याथिर्यों की नियमित उपस्थिति के निर्देश भी दिये गये।

धर्म परिवर्तन : दो महिला आरोपी गिरफ्तार

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने के एक प्रकरण में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो महिला आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि आरोपी महिलाओं द्वारा आर्थिक सहायता, इलाज तथा बीमारी दूर करने का झांसा देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए दबाव बनाया जा रहा था।

प्राप्त जानकारी के अनुसार 1 फरवरी 2026 को प्राथिर्या श्रीमती रूखमणी पाण्डेय (36 वर्ष) निवासी पदमनगर चरोदा, वार्ड क्रमांक 19, पुरानी भिलाई, जिला दुर्ग ने थाना पुरानी भिलाई में लिखित शिकायत दर्ज कराई। प्राथिर्या घरेलू कार्य एवं खाना बनाने का कार्य करती है। प्राथिर्या के अनुसार, 25 जनवरी 2026 (रविवार) को दो अज्ञात महिलाएं उसके घर आईं और ईसाई धर्म अपनाने पर बीमारी ठीक होने तथा आर्थिक सहायता मिलने का प्रलोभन दिया। प्राथिर्या द्वारा सहमति नहीं देने पर दोनों महिलाएं वहां से चली गईं। इसके पश्चात 01 फरवरी 2026 को वही दोनों महिलाएं पुनः प्राथिर्या के घर पहुंचीं और ईसाई धर्म अपनाने, बाइबिल पढ़ने, इलाज, आर्थिक सहायता एवं बेटी की शादी में सहयोग देने का लालच दिया। प्राथिर्या एवं परिजनों द्वारा विरोध किए जाने पर मामला बढ़ा, जिसके बाद प्राथिर्या ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

मामले में पुलिस द्वारा अपराध क्रमांक 71/2026, धारा 299 बीएनएस एवं धारा 04 छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

गिरफ्तार आरोपी में सारिका डाडिंगे (42 वर्ष), निवासी खुर्सीपार, प्रियंका साईमन (33 वर्ष), निवासी कुम्हारी शामिल हैं। दुर्ग पुलिस आम नागरिकों से अपील करती है कि किसी भी प्रकार के प्रलोभन, दबाव या बहकावे में न आएं। इस तरह की गतिविधियों की जानकारी तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस कंट्रोल रूम को दें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

महापौर बाघमार को जन्मदिन पर मिला लोगों का स्नेह

बधाई संदेश

मंत्री गजेंद्र यादव सहित भाजपा के दिग्गज नेताओं ने दी बधाई

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग नगर निगम की महापौर अलका बाघमार को जन्मदिन पर शनिवार को लोगों का अपार स्नेह मिला। फलस्वरूप सुबह से ही उनके सिविललाईन गौरव पथ स्थित आवास एफ 4 पर उन्हें बधाई देने वाले लोगों का तांता लगा रहा। बधाईयों का यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा।

अपने चहेते नेता और महापौर अलका बाघमार के जन्मदिन को यादगार बनाने भाजपा कार्यकर्ताओं व अन्य लोगों ने अपने-अपने अंदाज में महापौर का स्वागत कर जन्मदिन की खुशियां मनाई। किसी ने महापौर से केक कटवाया, तो किसी ने मिठाईयां बांटी। जन्मदिन के खुशियों के बीच कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रहे। जिससे महापौर आवास में दिनभर जन्मदिन की खुशियां गुलजार रही। लोग पहुंचते रहे और महापौर को गुलदस्ता भेंटकर जन्मदिन की बधाई दी और

उनके उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायू की कामना की गई। भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सुश्री सरोज पांडेय, डिप्टी सीएम, स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव के अलावा भाजपा के अन्य वरिष्ठ नेताओं ने महापौर को दूरभाष पर जन्मदिन की बधाई दी।

वहीं ग्रामीण विधायक ललित चंद्रकार, जिला भाजपा अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक, सभापति श्याम शर्मा, एमआईसी सदस्य नरेंद्र बंजारे, देवनारायण चंद्राकर, शेखर चंद्राकर, मनीष साहू, काशीराम कोसरे, ज्ञानेश्वर ताम्रकार, शिव नायक, नीलेश अग्रवाल, लीना दिनेश देवांगन, लीलाधर पाल, शशि साहू, हर्षिका सँभव जैन, पूर्व पार्षद अरुण सिंह, मंडल अध्यक्ष मनमोहन शर्मा, प्रदेश राइस मिल एसोसिएशन अध्यक्ष कांतिलाल बोथरा, जिला भाजपा उपाध्यक्ष अशोक राठी, दिनेश देवांगन, तेखन सिन्हा, भाजपा मंडल अध्यक्ष कमलेश फेकर, कौशल साहू, भाजपा नेता विनोद चंद्राकर, पार्षद सरिता चंद्राकर, साजन जोसेफ, कुलेश्वर साहू, गुलाब वर्मा, सविता साहू, रजनीश श्रीवास्तव, गायत्री वर्मा, कैट दुर्ग जिला महिला अध्यक्ष सुश्री पायल जैन, नीति बल्लेवार, पोषण साहू, रजा खोखर, समाजसेवी संजय बोहरा, सुनीता बोहरा, पूर्व पार्षद कांता साहू, रोमनाथ साहू, सीताराम ठाकुर सहित भाजपा, कांग्रेस के पार्षदगणों के अलावा नगर निगम के अधिकारी, कमर्चारीगण, भाजपा मण्डल अध्यक्षो और भाजपा के अन्य स्थानीय वरिष्ठ नेताओं ने महापौर के एफ 4 आवास कार्यालय सिविल लाइन पहुंचकर उन्हें जन्मदिन की बधाई दी। पूर्व विधायक अरुण वोरा, पूर्व महापौर आरएन वर्मा और कांग्रेस के अन्य नेता भी महापौर को बधाई देने उनके आवास पहुंचे थे।

महापौर अलका बाघमार के जन्मदिन को लेकर विभिन्न समाजिक, धार्मिक व व्यापारिक संगठनों के लोगों में भी खासा उत्साह रहा। फलस्वरुप संगठन के लोग बाजे-गाजे के साथ टोलियों में महापौर आवास पहुंचे और उन्हें बधाई दी। जन्मदिन पर लोगों से मिले स्नेह से गदगद महापौर अलका बाघमार द्वारा भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और शहर की जनता के प्रति आभार व्यक्त किया गया है।

सौगात आने वाले समय में प्राथमिकता क्रम में होगा आपके गांव में विकास कार्य

विधायक चंद्राकर ने कोनारी पहुँच मार्ग का किया भूमिपूजन

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

दुर्ग ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कोनारी में आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग ग्रामीण विधायक व राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष ललित चंद्राकर सम्मिलित हुए इस अवसर पर दुर्ग-बालोद मुख्य मार्ग से ग्राम कोनारी पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य का विधिवत भूमि पूजन एवं शिलान्यास किया गया। लगभग 0.925 किलोमीटर लंबी इस सड़क परियोजना की स्वीकृत लागत 140.77 लाख है, जो क्षेत्र के आवागमन एवं विकास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगी।

कार्यक्रम में विधिवत पूजा-अचर्ना के साथ नवीन विकास कार्यों की आधारशिला रखी गई। इस अवसर पर ग्राम सरपंच गुंजेश्वरी साहू जी, उपसरपंच सुरेश साहू, मंडल अध्यक्ष लिकेश्वर देशमुख जी, महामंत्री डिलेश साहू पुराण देशमुख, पंचगण हितेश्वरी साहू झुनिया बाई साहू देवनारायण साहू नंद साहू बीआर साहू , पारसचंद साहू विक्रम साहू बिसौह साहू , कांती साहू वासु चंद्राकर चित्ररेखा साहू राधाबाई साहू रविकांत साहू सोनिया साहू उपस्थित थे।

साथ ही लोक निर्माण विभाग से एसडीओ एस.एस. साहू एवं सब इंजीनियर सुनील धीड़ी की उपस्थिति रही। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामवासियों ने सहभागिता कर विकास कार्य के प्रति उत्साह और समर्थन व्यक्त किया।

इस अवसर पर दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने अपने संबोधन में कहा हमारी सरकार लगातार लोगों के जीवन के खुशियां लाने का काम कर रही और अन्तिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक विकास कैसे पहुंचे इस दिशा में निरन्तर कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है आपके गांव के विकास के लिए पैसे की कमी नहीं होगी इस बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आने वाले समय में प्राथमिकता क्रम में आपके गांव में विकास कार्य होंगे।

आगे श्री चंद्राकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मूलमंत्र है – सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। उनके मार्गदर्शन में हमारी सरकार पिछले 23 महीनों से सभी वर्गों के कल्याण के लिए सतत रूप से कार्य कर रही है।

हमने अन्नदाताओं के हित में कृषक उन्नति योजना, पक्का मकान देने हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना, माताओं और बहनों को सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना, तथा दूरस्थ अंचलों के विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षक युक्तियुक्तकरण जैसे कदम उठाए हैं। आप सभी को हार्दिक बधाई।

बिजली विभाग के साथ मना राज्य का रजत उत्सव : आदित्य नगर में जुटा जनसैलाब

नई दृष्टिबिंदु / दुर्ग

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में 'छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव 2026' के अंतर्गत 31 जनवरी को छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड, नगर संभाग दुर्ग द्वारा एक गरिमामयी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आदित्य नगर स्थित कुशाभाऊ ठाकरे भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में जनप्रतिधियों, विभागीय अधिकारियों और उपभोक्ताओं की भारी उपस्थिति रही।

कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दुर्ग शहर की महापौर श्रीमती अलका बाघमार उपस्थित रहीं। उनके साथ निगम सभापति श्याम शर्मा एवं विभिन्न वार्डों के पार्षदगण विशेष रूप से सम्मिलित हुए। विभाग की ओर से अधीक्षण अभियंता एस. मनोज, कायर्पालन अभियंता एस. के. महादुले, टी.एन.बंछोर और आर. के. दानी सहित समस्त

सहायक व कनिष्ठ अभियंता एवं कमर्चारी उपस्थित रहे। उत्सव के इस अवसर पर विभाग ने अपनी परंपरा और सेवा को सम्मान देते हुए विभाग के रिटायर्ड अधिकारियों एवं कमर्चारियों को शाल एवं श्रीफल भेंट कर उनकी दीर्घ सेवाओं के लिए सम्मानित किया ।

कार्यक्रम में ऊर्जा संरक्षण और समय पर भुगतान को प्रोत्साहित करने हेतु घरेलू, गैर-घरेलू, कृषि, बीपीएल श्रेणी एवं पीएम सूर्य घर योजना के 5-5 चयनित उपभोक्ताओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया।

परिसर में विभाग की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने हेतु विशेष स्टाल लगाए गए। बैनर और प्रोजेक्टर के माध्यम से उपभोक्ताओं को बिजली बचत, सुरक्षा और नई योजनाओं जैसे पीएम सूर्य घर के बारे में विस्तार से जागरूक किया गया। श्रीमती अलका बाघमार ने अपने संबोधन में विद्युत विभाग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि रजत महोत्सव के माध्यम से शासन की योजनाओं को जन-जन तक पहुँचाना एक सराहनीय कदम है।

कलेक्टर से हुई शिकायत, अब होगी कार्रवाई, पूर्व डिप्टी कलेक्टर कर चुकी है जांच

महिंद्रा शो रूम सहित 16 भूखंडों पर रोक होने के बाद भी निगम ने जारी किया बीबीसी

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

जिन जमीन में निर्माण पर कोर्ट ने रोक लगाया कर रखा है। शासन स्तर पर जिसकी जांच लंबित है। उन जमीनों पर निर्माण के लिए निगम प्रशासन ने भवन अनुज्ञा और भवन पूणर्तः प्रमाण जारी कर दिया है। अब इस मामले की कलेक्टर से शिकायत हो गई है। शिकातय में पूर्व डिप्टी कलेक्टर की जांच रिपोर्ट भी कलेक्टर को सौंपी गई है। इसके बाद से अब कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में ले लिया है। उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही कारर्वाई की जाएगी।

आप को बता दे कि सिविल अस्पताल सुपेला के बाजू में मर्च्युरी है। जहां जाने के

लिए सीधा रास्ता नहीं है। सामने में महेंद्रा शो रूम बना है। कुछ दिनों पहले कलेक्टर सिविल अस्पताल सुपेला का जांच करने पहुंचे। तब उन्होंने महेंद्रा शो रूम के आसपास निरीक्षण किया था। इसके बाद हेमंत निषाद ने कलेक्टर से सभी जरूरी दस्तावेज के साथ शिकायत की है। जिसमें उन्होंने बताया है कि

हाईकोर्ट ने 2001 में अस्पताल से लेकर कर्मा चौक तक कोई निर्माण एवं तोड़फोड़ नहीं करने का आदेश पारित किया था। यहां पर 16 भूखंडधारी है। जिनके विरूद्ध छत्तीसगढ़ शासन में जांच चल रही है। ऐसे में यदि हाईकोर्ट का आदेश यथावत है, तो यहां निर्माण नहीं किया जा सकता। लेकिन निगम के अफसरों ने भवन अनुज्ञा, भवन पूणर्तः प्रमाण पत्र तक जारी कर दिया है। भूखंडधारियों ने 4 से 5 मंजिल तक निर्माण कर लिए है।

2 कार्रवाई का निर्देश

न्यायालय ने 16 भूखंडो पर यथा स्थिति का आदेश है। यदि आदेश में कोई परिवर्तन या अंतिम आदेश पारित नहीं हुआ हो तो कायर्वाही किया जाना उचित होगा। पटवारी रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्र में काफी बड़े हिस्से में अवैध कब्जा प्रतित होता है। जिसकी जांच कर तत्काल कारर्वाई करने निर्देश दिया गया था।

जानिए मामला क्या है

साडा के समय 1989 में विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण की ओर से पट्टे पर हमारा ट्रांसपोर्ट कंपनी पाटनर एचएल सब्बरवाल पिता दीवानचंद नेहरू नगर को 2006 तक की अवधी के लिए पट्टा दिया गया था। सुपेला अस्पताल से कर्मा चौक तक सुधीर एक्स-रे व अन्य 16 लोगों को भूखंड दिया गया था। जो आवासी था, लेकिन गलती से आवासी सह व्यवसायिक के नाम से रजिस्ट्री हो गया। बाद में निगम भवन बनाने परमिशन दिया। जिसकी शिकायत के बाद जांच हुई और शासन ने कार्रवाई की थी।

डिप्टी कलेक्टर सौम्या चौरसिया ने की थी जांच

पूर्व डिप्टी सीएम सौम्या चौरसिया सन 2012 में दुर्ग जिले की डिप्टी कलेक्टर थी। तब उन्होंने इस मामले की जांच की थी। जिसकी रिपोर्टर उन्होंने तत्कालीन कलेक्टर को सौंपा था। जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि भूमि प्लाट नंबर 564 एवं 564 का टुकड़ा रकबा 16884 वर्ग फीट भूमि की रजिस्ट्री में करोड़ों रुपए की राजस्व क्षति हुई है। साथ ही आसपास के जगह पर अवैध कब्जा भी बताया गया है।

जानिए जांच रिपोर्ट में क्या है

1 गलत रजिस्ट्री- हमारा ट्रासपोर्ट कंपनी ने गलत दस्तावेज दिखाकर पंजीयन कराया और विभाग ने जांच भी नहीं की। एक भूखंड की दो एनओसी नहीं हो सकती। लेकिन दो अलग-अलग भूखंड बताकर, जीई रोड से दूरी बताकर रजिस्ट्री कराया। इससे शासन को लाखों रुपए का नुकसान हुआ है।

खास खबर

कपड़ा दुकान में लगी भीषण आग लाखों का सामान जलकर खाक

नई दृष्टिबिंदु / अंबिकापुर

बतौली थाना क्षेत्र अंबिकापुर अंतर्गत शांतिपारा स्थित अमित क्लॉथ में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही देर में दुकान में रखा लाखों रुपये का कपड़ा जलकर राख हो गया। सूचना मिलने पर दमकल टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। देर रात अचानक दुकान से धुआं उठने लगा, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इसकी जानकारी पुलिस और दमकल विभाग को दी। आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है। प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि जांच के बाद ही वास्तविक कारण सामने आएगा। अमित क्लॉथ दुकान में बड़ी मात्रा में कपड़े के बंडल और तैयार वस्त्र रखे हुए थे। आग इतनी भीषण थी कि दुकान की अधिकांश सामग्री पूरी तरह जल गई। नुकसान का अनुमान लाखों में लगाया जा रहा है, जिससे व्यापारी को भारी आर्थिक क्षति उठानी पड़ी है। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची। आग काफी फैल चुकी थी, फिर भी अधिकारियों ने लगातार प्रयास कर आग को नियंत्रित किया और आसपास की अन्य दुकानों में फैलने से रोका। देर रात तक राहत एवं नियंत्रण कार्य चलता रहा।

रतनजोत खा गए 24 बच्चे, बिगड़ी तबीयत

धमतरी। बोरझरा गांव में एक खौफनाक घटना सामने आई है, जब खेल-खेल में बच्चों ने रतनजोत के बीज खा लिए। इस घटना के बाद 24 से ज्यादा बच्चों ने उल्टी और चक्कर की शिकायत की, जबकि सात बच्चों की हालत गंभीर होने के कारण उन्हें तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। स्थानीय लोगों के अनुसार, यह घटना रविवार की दोपहर को तब हुई, जब बच्चे खेलते-खेलते गांव के पास उगे रतनजोत के पेड़ के बीजों को खाने लगे। बच्चों को इस बीज के हानिकारक प्रभाव का अंदाजा नहीं था। कुछ ही समय बाद, कई बच्चों ने उल्टी, पेट दर्द और चक्कर आने की शिकायत की। ग्रामीणों ने तुरंत इसकी जानकारी बच्चों के माता-पिता को दी। घटना के तुरंत बाद बोरझरा गांव के लोगों ने जिला अस्पताल को सूचित किया। अस्पताल प्रशासन ने बच्चे को तुरंत आपातकालीन वार्ड में भर्ती कर, उनका प्राथमिक उपचार शुरू किया।

कबीरपंथ का छग के जनजीवन में व्यापक प्रभाव विकसित प्रदेश बनने तेजी से अग्रसर-सीएम साय

संत समागम समारोह की राशि 50 लाख से बढाकर 75 लाख करने की घोषणा

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को बहुत आगे ले जाना है और विकसित प्रदेश के रूप में खड़ा करना है। उन्होंने संत समागम समारोह दामाखेड़ा की राशि 50 लाख रूपये से बढाकर 75 लाख रूपये करने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कल रविवार को कबीर धर्मनगर दामाखेड़ा में माघ पूणिर्मा के अवसर पर आयोजित सतगुरु कबीर संत समागम समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने पंथ उदित मुनि नाम साहेब, पंथ प्रकाश मुनि नाम साहब को चादर श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया और प्रदेश की खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय माघ पूणिर्मा की शुभकामनायें देते हुए कहा कि कबीर धर्म नगर दामाखेड़ा का संत समागम समारोह हर साल भव्य होते जा रहा है जो लोगों में बढ़ते आस्था का प्रतीक है।

मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि कबीरपंथ का छत्तीसगढ़ के जनजीवन में व्यापक प्रभाव है इसलिए यहां के लोग शांति प्रिय है। उन्होंने कहा कि वे बचपन से ही कबीर पंथ से परिचित है और उनके गांव बगिया में भी 8-10 कबीर पंथी परिवार है। उन्होंने दामाखेड़ा का नाम कबीर धर्मनगर करने के संबंध में बताया कि राजपत्र में प्रकाशन हेतु अंतिम प्रक्रिया जारी है। श्री साय ने कहा कि डबल इंजन की सरकार से लोगों को सीधा फायदा मिल रहा है। अब मुख्यमंत्री ने कहा कि छतीसगढ़ के विकास की बाधा की नक्सलवाद अब जल्द ही जड़ से समाप्त होने वाला है। नक्सलवाद का प्रदेश से 31 मार्च 2026 तक समूल नष्ट हो जाएगा। हमने जनता से किया वादा को तेजी से पूरा किया है।

उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि पंथ उदित मुनि नाम साहब का चादर तिलक अद्भुत और अलौकिक रहा। पंथ श्री ने वृक्षारोपण, समाज सेवा, नशामुक्ति एवं युवा उत्थान के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। उन्होंने पंथ श्री का दर्शन कर प्रदेश की सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णु देव साय कबीर आश्रम के विभिन्न विकास कार्यों को लेकर हमेशा चिंतित रहते है और शीघ्र पूरा करने के निर्देश देते हैं। कार्यक्रम को खाद्य मंत्री दयाल दास बघेल, भाटापारा विधायक इंद्र साव ने भी सम्बोधित किया।

समारोह में पंथश्री प्रकाश मुनि नाम साहब ने मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का कबीरपंथी समाज की ओर से आत्मीय स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष माघ मेला के प्रथम दिन बसंत पंचमी के अवसर पर कबीर पंथ के नये संवाहक 16 वें वंशाचार्य पंथी उदित मुनि नाम साहेब का चादर तिलक संपन्न हुआ। उन्होंने बताया कि इस वर्ष देश के विभिन्न प्रांतों के साथ ही विदेशों से भी कबीरपंथी संत समागम मेला में आये हैं। समारोह को शासन प्रशासन का भरपूर सहयोग मिला है।

इस अवसर पर पंथश्री उदित मुनि नाम साहब, गुरूगोसांई भानुप्रताप साहब, विधायक श्रीमती भावना बोहरा, ईश्वर साहु, पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, पूर्व विधायक शिवरतन शर्मा सहित सदगुरू कबीर धमर्दास साहेब वंशावली प्रतिनिधि सभा के प्रतिनिधिगण, अधिकारी-कमर्चारी एवं बड़ी संख्या में कबीरपंथ के अनुयायी उपस्थित थे।

---

43 वर्षो की भरोसेमंद सेवा का उत्सव, जयदीप गैस एजेंसी के नवनिर्मित शोरूम का किया गया उद्घाटन

नई दृष्टिबिंदु / भिलाई

Megh Ganga Group के अंतर्गत संचालित जयदीप गैस एजेंसी (HP Gas) ने अपनी 43 वर्षों की सफल और भरोसेमंद सेवा यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ते हुए सेक्टर-10, मार्केट, भिलाई में अपने नव-निर्मित (Renovated) शोरूम का भव्य उद्घाटन किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मंगेश एम. डोंगरे, मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधक, रायपुर LPG क्षेत्रीय कार्यालय उपस्थित रहे। कार्यक्रम की गरिमामयी उपस्थिति मनोज कुमार मंडल, वरिष्ठ क्षेत्रीय बिक्री प्रबंधक, भिलाई LPG द्वारा की गई।

अपने संबोधन में दुर्ग महापौर श्रीमती अलका बाघमार ने कहा कि एलपीजी केवल एक ईंधन नहीं, बल्कि हर घर की सुरक्षा, सुविधा और जीवनशैली का अभिन्न हिस्सा है, जिसे हर घर तक पहुचाने की योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी चलाया गया

।जयदीप गैस एजेंसी ने पिछले 43 वर्षों से जिस निष्ठा और भरोसे के साथ समाज की सेवा की है, वह सराहनीय है।

Megh Ganga Group के चेयरमैन मनीष पारख ने इस अवसर पर समाज के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि हमारा सफर केवल गैस सिलेंडर पहुँचाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर घर से एक रिश्ता बनाने का रहा है।समाज द्वारा दिए गए विश्वास ने ही हमें आज इस मुकाम तक पहुँचाया है। नवनिर्मित शोरूम को आधुनिक सुविधाओं, बेहतर ग्राहक अनुभव और तेज सेवा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, ताकि उपभोक्ताओं को पहले से अधिक सहज और भरोसेमंद सेवाएँ उपलब्ध कराई जा सकें।

कार्यक्रम का संचालन निरमल पारख एवं संजय देशलहारा के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ।RSVP के रूप में मनीष पारख, नितेश पारख, निलेश पारख, अविश पारख एवं Megh Ganga परिवार उपस्थित रहे। कार्यक्रम में क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों, उपभोक्ताओं और व्यापारिक सहयोगियों की उपस्थिति ने आयोजन को विशेष बना दिया। अंत में जयदीप गैस एजेंसी के सभी सदस्यों ने यह संकल्प दोहराया कि आने वाले वर्षों में भी हम उसी ईमानदारी, जिम्मेदारी और सेवा भावना के साथ हर घर तक सुरक्षित और भरोसेमंद एलपीजी सेवा पहुँचाते रहेंगे।

मेघ गंगा ग्रुप दुर्ग शहर की एक प्रख्यात व्यवसायिक समूह है, जिसके नींव मनीष पारख जी द्वारा रखा गया, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं देने प्रतिबद्ध है। जिसके अंतर्गत अविश एडुकॉम, लाइफकेयर डायग्नोसिस – NABL, NABH की मान्यता, महावीर ज्वैलर्स, जयदीप गैस एजेंसी, डिजाइनों डिजाइन एनीथिंग, TISD - द इंटरनेशनल स्कुल ऑफ डिजाइन, इमेजेस, KAC गेटवे ऑफ ग्लोबल एजुकेशन, U³f¢J¸f कैफे शामिल है, FADE आते है, मेघ गंगा ग्रुप के ये सभी स्तंभ सामुदायिक विकास और सामाजिक दायित्वों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं।

पिछले 2 वर्ष 2025 में मनीष पारख के निर्देशन में मेघगंगा ग्रुप अग्रसर है : मोर शहर मोर जिम्मेदारी के अंतर्गत दुर्ग शहर के गांधी चौक , शहीद चौक दुर्ग, राजेंद्र प्रसाद चौक, शेप ब्रिज स्थित चौक का पुनर्निर्माण। स्वच्छता के मापदण्डों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राज्यपाल छत्तीसगढ़ द्वारा सम्मानित ।स्वास्थ क्षेत्र में विशेष योगदान हेतु धन्वंतरि अवार्ड से सम्मानित किया गया। लाइफकेयर डायग्नोसिस में नवीन टेक्नोलॉजी और महत्वपूर्ण मशीनों का इंस्टालेशन किया गया ।

राष्ट्रपति मुर्मू की ओडिशा व छग की 6 दिवसीय यात्रा आज से

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर/ओड़िशा

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु आज से 7 फरवरी 2026 तक ओडिशा और छत्तीसगढ़ का छह दिवसीय दौरा करेंगी। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य शिक्षा, आदिवासी कल्याण, संस्कृति को बढ़ावा और आदिवासी बहुल क्षेत्रों में विकास कार्यों पर ध्यान केंद्रित करना है। राष्ट्रपति मुर्मु आज शाम को भुवनेश्वर पहुंचेंगी। 3 फरवरी को वह बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय की दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। वहीं वह विश्वविद्यालय के नए बनाए गए ऑडिटोरियम का उद्घाटन भी करेंगी। यह कदम पूर्वी भारत में उच्च शिक्षा के ढांचे को मजबूत करने की सरकार की प्राथमिकता को दर्शाता है।

4 फरवरी को वह मयूरभंज जिले के राइरांगपुर में होंगी, जो आदिवासी इलाकों में आता है। राष्ट्रपति प्रतिष्ठित आदिवासी नेता भान्जबीर सुनाराम सोरेन की प्रतिमा का अनावरण करेंगी। इसके अलावा वह महुलदीहा के सरकारी गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल की छात्राओं से भी बातचीत करेंगी। इसके बाद वह कई परियोजनाओं का उद्घाटन और भूमि पूजन करेंगी, जिनमें सरकारी आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, ओडिशा कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के परिसर में विकास कार्य, एक आचर्री सेंटर, शहर को सुशोभित करने और ड्रेनेज सुधार कार्य, विभिन्न कॉर्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी योजनाएं, एमएससीबी विश्वविद्यालय सूचना प्रौद्योगिकी कैंपस शामिल हैं।

ये परियोजनाएं आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, शहरी सुविधाओं और प्रौद्योगिकी के समग्र विकास को बढ़ावा देने की दिशा में उठाए गए कदम हैं। 6 फरवरी को राष्ट्रपति सिमलिपाल में आदिवासी समुदायों की महिलाओं और युवाओं से सीधे मिलेंगी।

अव्यवस्था अभियान चलाकर 15 दिन और धान खरीदी की जाये

सरकार ने षडयंत्र पूर्वक लक्ष्य से कम धान खरीदा, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बंद कर दिया

नई दृष्टिबिंदु / रायपुर

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने पत्रकारवार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी बंद कर दिया है। लेकिन अभी भी प्रदेश के लाखों किसान अपना धान नहीं बेच पाये है। इस साल सरकार ने मात्र 53 दिन ही धान खरीदा। अंतिम तिथि भी 31 जनवरी थी, लेकिन अंतिम 2 दिन शनिवार और रविवार होने के कारण खरीदी नहीं हुई। पूर्व में घोषित 75 दिन भी पूरी खरीदी नहीं किया गया। इस वर्ष सरकार के द्वारा घोषित लक्ष्य 165 लाख मीट्रिक टन था, लेकिन सरकार ने मात्र 139 लाख 85 हजार मीट्रिक टन ही धान खरीदी किया गया। लक्ष्य से 25 लाख मीट्रिक टन कम धान खरीदी किया गया। पिछले साल सरकार ने 149 लाख मीट्रिक टन धान खरीदा था, इस वर्ष पिछले साल के मुकाबले 9 लाख 15 हजार मीट्रिक टन कम

की खरीदी की गयी।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कुल 27 लाख किसानों का पंजीयन हुआ था, जिसमें से 2.5 लाख किसान अपना धान नहीं बेच पाये। लगभग 5 लाख किसानो का एग्रीस्टेक पोर्टल की परेशानी के कारण पंजीयन नहीं हुआ। किसानों को धान बेचने से रोकने बिना सहमति जबरिया रकबा सरेंडर करवा दिया गया। पूर्व से जारी टोकन को निरस्त करवाया गया। हजारो किसान सरकार के इस षडयंत्र का शिकार हुये। धान का टोकन नहीं मिलने, धान की खरीदी नहीं होने के कारण प्रदेश के महासमुंद, कवर्धा, कोरबा, जैसे स्थानों पर अनेको किसानों ने आत्महत्या का प्रयास किया। एक ने आत्महत्या भी किया। यह बताता है कि प्रदेश में धान खरीदी के कारण किसान परेशान हुये। सिर्फ नारायणपुर, बलरामपुर, बस्तर में पिछले साल के लगभग बराबर धान की खरीदी हुई, शेष सभी जिलों में 5 प्रतिशत से लेकर 32 प्रतिशत तक कम खरीदी सरकार ने किया।

गरियाबंद की घटना बिगड़ती कानून व्यवस्था का परिणाम

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि गरियाबंद से बेहद ही दुर्भाग्यजनक खबर आ रही है, वहां के दुतकैया गांव में एक समुदाय के घरों को जला दिया गया। वहां पर एक अपराधी के द्वारा फैलाए जा रहे आतंक के कारण यह घटना घटी। यह घटना पुलिस और सरकार की लापरवाही का परिणाम है। पुलिस सचेत होती अराजक तत्व पर कायर्वाही करती तो शायद यह घटना नहीं होती। मै दोनों पक्षों से शांति की अपील करता हूं तथा घटना की न्यायिक जांच की मांग करता हूं। इसके पहले बलौदाबाजार, कवर्धा, बलरामपुर के बाद गरियाबंद में जनता ने कानून हाथ में लिया है। इससे साफ है लोगों का सरकार और उसके कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है।

बजट से छत्तीसगढ़ ठगा गया

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कल मोदी सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ। उसमें एक बार फिर छत्तीसगढ़ का उल्लेख सिर्फ एक जगह है। विशेष कारीडोर में वह भी छत्तीसगढ़ की जनता के लिये नहीं छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा का दोहन उद्योगपति मित्र आसानी से कर सके। इसलिये राज्य के विकास के लिये बस्तर, सरगुजा क विकास के लिये बजट में कुछ नहीं है।

एपस्टीन फाईल को लेकर भाजपा चुप क्यों है

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि एपस्टीन फाइल के बारे में मोदी और भाजपा चुप क्यों है इस मामले में प्रधानमंत्री और भाजपा को स्पष्टीकरण देना चाहिये की एपस्टीन फाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम से देश की छवि धूमिल हो रही है।

पत्रकार वार्ता में प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह गैदू, प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला, महामंत्री दीपक मिश्रा, सकलेन कामदार, वरिष्ठ प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर, सुरेन्द्र वर्मा, अशोक राज आहूजा, अमरजीत चावला, प्रवक्ता सत्य प्रकाश सिंह, अजय गंगवानी उपस्थित थे।

पीआरजीआई सं.-CTHIN/25/A3746 यह हिंदी सांध्य दैनिक समाचार पत्र नई दृष्टिबिंद स्वामी एवं प्रकाशक आलोक तिवारी द्वारा समय दर्शन प्रिंटर्स एंड पब्लिशर्स द्वारा प्लॉट नं. 339/6, गली नं. 02, पाटन, थाना उतई, दुर्ग, (छ.ग.)-491111 से मुद्रित करवा कर। 80/बी, मैत्री विहार, राधिका नगर, सुपेला, भिलाई, जिला दुर्ग, (छत्तीसगढ़)-490023 से प्रकाशित संपादक आलोक तिवारी मो. 7415469100 (समाचार चयन के लिए पीआरबी एक्ट के तहत जिम्मेदार), समस्त विवादों का निपटारण न्यायालयीन क्षेत्र दुर्ग होगा।